

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47, नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22, 1969/अग्रहायणा 1, 1891
No. 47 NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22, 1969/AGRAHAYANA 1, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (सब क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर)

केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएँ।

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 6th November 1969

S.O. 4634.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission, in consultation with the Administration of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, hereby nominates Shri K. Damodara Menon, Administrator, Union Territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands from the afternoon of the 1st November, 1969 vice Shri C. H. Naire.

[No. 154/27/69.]

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1969

एस० ओ० 4634.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13-क की उधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, लक्कादीव, मिनीकीय और अमीनदीवी द्वीपों के प्रशासन से परामर्श करके, श्री सी० एच० नैर के स्थान पर श्री के० दामोदर मॅनन, प्रशासक, लक्कादीव, मिनीकीय और अमीनदीवी द्वीप संघ-राज्यक्षेत्र, को 1 नवम्बर, 1969 के अपराह्न स लक्कादीव, मिनीकीय और अमीनदीवी द्वीप संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकार के रूप में एतद्वारा नाम निर्देशित करता है।

[सं० 154/27/69]

आदेश से,

क० एस० राजगोपालन, सचिव।

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 4635.—In pursuance of the provisions contained in sub-section (1) of Section 13AA of the Representation of the People Act, 1950, and in supersession of its notification No. 508/J&K/66, dated the 26th December, 1966, the Election Commission, in consultation with the State Government hereby designates the Deputy Commissioner of each district in the State of Jammu and Kashmir to be the District Election Officer for that district.

[No. 508/J&K/69(1).]

By order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

ORDERS

New Delhi, the 18th October 1969

S.O. 4636.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Om Prakash, Medical Practitioner, Dhuri Gate, Sangrur a contesting candidate for the mid-term general election held in February, 1969 to the Punjab Legislative Assembly from Sangrur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder and the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure;

And whereas the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Om Prakash to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/92/69(9).]

आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1969

एस० ओ० 4636.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1969 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन के लिए संगरूर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ओम् प्रकाश, मेडिकल प्रैक्टिसनर, धुरी गेट, संगरूर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है और उन्हीं अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः यह, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री ओम् प्रकाश को संपद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० पंजाब-वि० सं०/92/69(9).]

New Delhi, the 25th October 1969

S.O. 4637.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dalip Singh, Village and P.O. Vaitoha, Tehsil Patti, District Amritsar a contesting candidate for the mid-term general election held in February, 1969 to the Punjab Legislative Assembly from Vaitoha constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dalip Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/18/69(10).]

By Order,

ROSHAN LAL, Secy.

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1969

एस० प्रो० 4637.—प्रतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1969 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन के लिए बालटोहा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दलीप सिंह ग्राम व डाकघर बालटोहा, तहसील पट्टी जिला अमृतसर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है और उसने अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री दलीप सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० पंजाब-वि० सं०/18/69(10)]

आदेश से,

रोशन लाल, सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th November 1969

S.O. 4638.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Civil Courts) Regulation, 1965 (9 of 1965), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 1154, dated the 19th March, 1969, namely:—

Amendment

In the Table appended to the said notification, against the entry relating to "2. Court of Subordinate Judge" for the words "The Island of Kavaratti", in column (2), the words "Kozhikode in Kerala State, the Island of Kavaratti" shall be substituted.

[No. F. 9/1/69-UTL.]

P. N. KAUL, Dy. Secy.

NOTICE

New Delhi, the 6th November 1969

S.O. 4639.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri D. D. Kakkar, Advocate, 36/9, East Patel Nagar, Delhi-8, for appointment as a notary to practise in Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. 22/30/69-Judl.III.]

K. THYAGARAJAN,
Competent Authority.

नोटिस

नई दिल्ली 6 नवम्बर 1969

एस० एन० 4639:—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को डी० डी० कक्कर, अधिवक्ता, 36/9, पूर्वी पटेल नगर, दिल्ली 8 ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, दिल्ली में लेख्य प्रमाणक (नोटरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियाँ हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिखकर भेज दिये जायें।

[सं० 22/30/69-न्यायिक]

के त्यागराजन,
सक्षम प्राधिकारी।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 22nd October 1969

S.O. 4640.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration Act 1922 (VII of 1922) the Central Government hereby appoints Shri V. N. Mokashi,

Public Relations Officer, Regional Passport and Emigration, Office, Delhi to be Protector of Emigrants, Delhi in addition to his own duties with effect from 3rd October, 1969, vice Shri M. M. Saigal, relieved of his duties on transfer.

[No. CP & EO/18/69.]

M. L. KHOSLA, Attache (PVA).

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1969

एस० ओ० 4640 :—उत्प्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का सातवां) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा श्री बी० एन० मोकाशी, जन सम्पर्क अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, दिल्ली को, उनके कार्य के अतिरिक्त, 3 अक्टूबर, 1969 से उत्प्रवासी संरक्षक भी नियुक्त करती है। श्री बी० एन० मोकाशी श्री एम० एम० सेगल की जगह नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने स्थानान्तरण हो जाने पर अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

[सं० सी० पी० आर ई० ओ० /18/69]

एम० एल० खोसला,

सहचारी (पीबीए)।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 5th November 1969

S.O. 4641.—Whereas on an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government has made, under sub-section (2) of the said section 45 an order of moratorium in respect of the Bank of Behar Limited, Patna, under sub-section (2) of the said section.

And whereas the Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 45 of the said Act has prepared a scheme for the amalgamation of the Bank of Behar Limited, Patna with the State Bank of India.

And whereas the Reserve Bank after having sent the said scheme in draft to the banks concerned in accordance with the provisions of sub-section (6) of the said section and after having considered the suggestions and objections received in regard to the said scheme has modified that scheme and forwarded it to the Central Government for sanction.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 45 of the said Act, the Central Government hereby sanctions the scheme and subject to the terms and conditions hereinafter mentioned.

(1) The Bank of Behar Limited, shall be the transferor bank and the State Bank of India shall be the transferee bank.

(2) As from the date which the Central Government may specify under sub-section (7) of section 45 of the said Act (hereinafter referred to as the prescribed date), all rights, powers, claims, demands, interests, authorities, privileges, benefits, assets and properties of the transferor bank, movable and immovable, including premises subject to all incidents of tenure and to the rents and other sums of money and covenants reserved by or contained in the leases or agreements under which they are held, all office furniture, loose equipment, plant, apparatus and appliances, books, papers, stocks of stationery, other stocks and stores, all investments in stocks, shares and securities, all bills receivable in hand and in transit, all cash in hand and on current or deposit account (including money at call or short notice) with banks, bullion, all book debts, mortgage debts and other debts

with the benefit of securities, or any guarantee therefor, all other, if any, property rights and assets of every description including all rights of action and benefit of all guarantees in connection with the business of the transferor bank shall, subject to the other provisions of this scheme, stand transferred to, and become the properties and assets of, the transferee bank; and as from the prescribed date all the liabilities, duties and obligations of the transferor bank shall be and shall become the liabilities, duties and obligations of the transferee bank to the extent and in the manner provided hereinafter.

Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect immediately before the prescribed date shall be effective to the extent and in the manner hereinafter provided against or in favour of the transferee bank and may be acted upon as if instead of the transferor bank the transferee bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee bank.

If on the prescribed date any suit, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the transferor bank is pending, the same shall not abate, or be discontinued or be in any way prejudicially affected, but shall subject to the other provisions of this scheme, be prosecuted and enforced by or against the transferee bank.

If according to the laws of any country outside India the provisions of this scheme, by themselves, are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the transferor bank to or in the transferee bank, the affairs of the transferor bank in relation to such asset or liability shall, on the prescribed date, stand entrusted to the chief executive officer for the time being of the transferee bank and the chief executive officer may exercise all powers and do all such acts and things as would have been exercised or done by the transferor bank for the purpose of effectively winding up its affairs. The chief executive officer shall take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of effecting such transfer or vesting and in connection therewith the chief executive officer may, either himself or through any person authorised by him in this behalf, realise any asset or discharge any liability of the transferor bank and transfer the net proceeds thereof to the transferee bank.

(3) The books of the transferor bank shall be closed and balanced and balance-sheets prepared in the first instance as at the close of business on the 9th August, 1969 and thereafter as at the close of business on the date immediately preceding the prescribed date and the balance-sheets shall be got audited and certified by a chartered accountant or a firm of chartered accountants approved or nominated by the Reserve Bank of India for the purpose.

A copy each of the balance-sheets of the transferor bank prepared in accordance with the provisions of the foregoing sub-paragraph, shall be filed by the transferor bank with the Registrar of Companies as soon as possible after it has been received and thereafter the transferor bank shall not be required to prepare balance-sheets or profit and loss accounts, or to lay the same before its members or file copies thereof with the Registrar of Companies or to hold any annual general meetings for the purpose of considering the balance-sheet and accounts or for any other purpose or to comply with the provisions of section 159 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and it shall not thereafter be necessary for the Board of Directors of the transferor bank to meet as required by section 285 of that Act.

(4) The transferee bank shall, in consultation with the transferor bank, value the property and assets and reckon the liabilities of the transferor bank in accordance with the following provisions, namely,—

- (a) investments including Government securities shall be valued at the market rates prevailing on the day immediately preceding the prescribed date:

Provided that the securities of the Central Government such as Post Office Certificates, Treasury Savings Deposit Certificates and any other securities or certificates issued under the small savings scheme of the Central Government shall be valued at their face value or the encashable value as on the said date, whichever is higher.

- (b) where the market value of any Government security such as the Zamindari Abolition Bonds or other similar security in respect of

which the principal is payable in instalments is not ascertainable or is, for any reason, not considered as reflecting the fair value thereof or as otherwise appropriate, the security shall be valued at such an amount as is considered reasonable having regard to the instalments of principal and interest remaining to be paid, the period during which such instalments are payable, the yield of any security issued by the Government to which the security pertains and having the same or approximately the same maturity, and other relevant factors;

- (c) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, the investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period;
- (d) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not ascertainable, only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable, having regard to the financial position of the issuing concern, the dividends paid by it during the preceding five years and other relevant factors;
- (e) premises and all other immovable properties and any assets acquired in satisfaction of claims shall be valued at their market value;
- (f) furniture and fixtures, stationery in stock and other assets, if any, shall be valued at the written down value as per books or the realisable value as may be considered reasonable;
- (g) advances, including bills purchased and discounted, book debts and sundry assets, will be scrutinised by the transferee bank and the securities, including guarantees, held as cover therefor examined and verified by the transferee bank. Thereafter, the advances, including portions thereof, will be classified into two categories, namely, "Advances considered good and readily realisable" and "Advances considered not readily realisable and/or bad or doubtful of recovery".
- (h) liabilities for the purposes of this scheme shall include all contingent liabilities which the transferee bank may reasonably be expected or required to meet out of its own resources on or after the prescribed date.

II. Where the valuation of any asset cannot be determined on the prescribed date, it may, with the approval of the Reserve Bank of India be treated partly or wholly as an asset realisable at a later date.

In the event of any disagreement between the transferee bank and the transferor bank as regards the valuation of any asset or the classification of any advance or the determination of any liability, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India, whose opinion thereon shall be final:

Provided that until such an opinion is received, the valuation of the item or portion thereof by the transferee bank shall provisionally be adopted for the purpose of this scheme.

It shall be competent for the Reserve Bank in the event of its becoming necessary to do so, to obtain such technical advice as it may consider to be appropriate in connection with the valuation of any such item of asset or determination of any such item of liability, and the cost of obtaining such advice shall be payable in full out of the assets of the transferor bank.

The valuation of the assets and the determination of the liabilities in accordance with the foregoing provisions shall be binding on both the banks and the members and creditors thereof.

(5) In consideration of the transfer of the property and the assets of the transferor bank to the transferee bank the transferee bank shall discharge the liabilities of the transferor bank to the extent mentioned in this and the following clauses, namely,—

- (a) any sums deposited by any employee of the transferor bank with that bank as staff security deposits together with interest if any accrued thereon up to the prescribed date and all other outside liabilities as on the prescribed date excluding deposits shall be paid or provided for in full.

Explanation.—For the purposes of this clause, interest payable on a deposit up to the prescribed date shall be regarded as part of the concerned deposit;

(b) in respect of every savings bank account or current account or any other deposit including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposit by whatever name called with the transferor bank and every other account not covered by clause (a), including interest to the extent payable under this scheme, the transferee bank shall open with itself on the prescribed date a corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto the *pro-rata* share available in respect of each of the accounts out of the assets referred to in paragraph (4) as valued for the purposes of this scheme on the prescribed date, after excluding from the said assets as so valued the advances considered not readily realisable or bad or doubtful of recovery, any asset or portion of an asset not valued on the prescribed date and any amount needed for the payments or provisions mentioned at clause (a) above and after adding to the said assets as so valued the aggregate amount of the payments made in terms of clause (a)(i) of paragraph 2 of the moratorium order dated the 8th August, 1969, issued to the transferor bank:

Provided that any payment made from a deposit account on or after the 10th August, 1969, and before the prescribed date, shall be reckoned towards the amount to be credited under this sub-paragraph and, accordingly the amount to be credited shall be the *pro rata* share less the amount of such payment:

Provided further that where the transferee bank entertains a reasonable doubt as to the correctness of the entries made in any particular the credit to be made in that account in terms of clause (b) above till the transferee bank is able to ascertain the correct balance in such account.

Explanation.—The term 'pro rata' shall, in so far as it occurs in this paragraph, mean in proportion to the respective amounts remaining due as at the close of business on the 9th August, 1969, (inclusive of interest payable up to that date) and shall, in so far as it occurs elsewhere in this scheme, mean 'in proportion to the respective amounts remaining due at the time of the payment or distribution';

(c) after the credits referred to in clause (b) above have been afforded, the transferee bank shall, with the least possible delay but in any case not later than three months from the prescribed date, furnish to the deposit Insurance Corporation established under the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (47 of 1961, hereinafter referred to as the Corporation) a list complying in all respects with the requirements of sub-section (1) of section 18 of that Act and thereafter whenever amounts referred to in sub-section (2) of section 18 of that Act are received from the Corporation, the transferee bank shall credit each of the accounts referred to in clause (b) above, within seven days from the date or dates on which the amounts are received, to the extent of the sums due to that account in accordance with sub-section (2) of section 18 of that Act:

Provided that—

(i) if any account referred to in clause (b) has been closed or has matured for payment at the time when any amount for credit to that account is received from the Corporation, the payment to the person entitled to the said amount shall be made by the transferee bank in cash;

(ii) in case the person entitled to any amount referred to in clause (b) cannot be found or is not readily traceable, provision for the amount due to such person shall be made and accounted for separately in the books of the Corporation itself and it shall not be necessary for the Corporation to pay the amounts to the transferee bank unless the person entitled to the amount is found or traced and the Corporation has decided to make the payment in respect of that person through the transferee bank;

(d) on the prescribed date, the entire amount of the paid-up capital and reserves of the transferor bank shall be treated as provision for bad

and doubtful debts and depreciation in other assets of the transferor bank and the rights of the members of the transferor bank shall, in relation to the transferee bank, be as provided for in paragraph (6) below.

(6) In respect of—

- (A) every account mentioned in clause (b) of the preceding paragraph, the balance in the account, if any, remaining uncredited in terms of that clause and clause (c) and
- (B) every share in the transferor bank, the amount of which was treated as paid up towards share capital by or on behalf of each shareholder immediately before the prescribed date and/or the amount paid on account of the calls made by the transferee bank in pursuance of sub-clause (i) below,

shall be treated as a collection account and shall be entered as such in the books of the transferee bank and payments against the account shall be made in the following manner, namely,—

(i) the transferee bank may,—

- (a) in the first instance, call upon every person who on the prescribed date was registered as the holder of a deferred share in the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such shares and the calls in arrears, if any and thereafter, if it is found to be so necessary, every person who was, as on the prescribed date, registered as the holder of an ordinary share of the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares or the calls in arrears, if any; and
- (b) take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts due under this clause, together with interest at six per cent per annum for the period of the default;
- (ii) the transferee bank shall, in respect of the advances, bills purchased and discounted, book debts and sundry debts and other assets, which are classified as "Advances considered not readily realisable and/or bad or doubtful of recovery", or which are or may be realisable wholly or partly after the prescribed date in terms of paragraph (4) above, take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce payment, provided, however, that if the amount of a debt or asset exceeds Rs. 10,000, the transferee bank shall not, except with the approval of the Reserve Bank of India,—
 - (a) enter into a compromise or arrangement with the debtor or any other person or write off any such debt or asset;
 - (b) sell or otherwise dispose of any securities transferred to it or any asset taken over by it;
- (iii) the transferee bank shall in addition take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts, if any, awarded as damages by the High Court against any promoter, director, manager or other officer of the transferor bank under section 45L of the Banking Regulation Act, 1949, read with section 45H thereof and also with section 543 of the Companies Act, 1956;
- (iv) the transferee bank may, out of the realisations effected by it on account of the items mentioned in sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, make payment or provision in respect of any contingent liability to the extent that the provision made therefor under paragraph (5)(a) proves to be inadequate, as also with the prior approval of the Reserve Bank, in respect of any liability whether contingent or absolute which was not assessed in terms of paragraph (4) above and has arisen or been discovered on or after the prescribed date;
- (v) the transferee bank shall out of the realisations effected by it on account of the items mentioned in sub-clauses (i), (ii) and (iii) above after

deducting therefrom the expenditure incurred for the purpose and, with the approval of the Reserve Bank of India, such other expenses as may be considered reasonable and the amount appropriated therefrom in terms of clause (iv) above, or out of the balance, if any, which may be available from out of the provision in respect of contingent liabilities as reckoned for the purposes of this scheme after the extent of such liabilities has finally been ascertained,—

- (a) pay to the Corporation the amount received by the transferee bank from the Corporation under sub-section (2) of section 18 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 and the amount, if any, provided for by the Corporation; and
- (b) pay, in the case of depositors in respect of whom no amounts have been received by the transferee bank from the Corporation, the amounts due in respect of the collection accounts, and in the case of depositors in respect of whom any amounts have been received by the transferee bank from the Corporation or have been provided for by the Corporation the balance if any due to them in their collection accounts after the amounts due from the said accounts to the Corporation in respect of the payment made or provided for by the Corporation have first been paid in accordance with the provisions of sub-clause (a) above :

Provided that the amount due to the Corporation shall, if it becomes necessary so to do, be provided for in the books of the transferee bank and be paid to the Corporation in the manner specified in clause (b) of regulation 22 of the Deposit Insurance Corporation General Regulations, 1961:

Provided further that the transferee bank shall make the payments referred to in clause (b) above,—

- (i) if the corresponding or similar account mentioned in clause (b) of paragraph (5) has not been closed or has not matured for payment, by credit to that account, and
- (ii) if the said account has been closed or has matured for payment, in cash;
- (vi) the amounts due to the Corporation in terms of sub-clause (a) of clause (v) above and the amounts due to the collection accounts of the depositors in terms of sub-clause (b) of that clause shall rank equally among themselves, and if they cannot be paid in full shall abate in equal proportions;
- (vii) after the payments referred to in clause (v) of this paragraph have been made or provided for in full, the transferee bank shall, out of the balance of the amounts referred to in clause (v) which may be available to it, make payments *pro rata* towards the amounts, if any, due to the accounts of the former shareholders of the transferor bank in the manner and to the extent specified below :
 - (a) in the first place, the amounts, if any, due to the accounts of the former preference shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made;
 - (b) in the second place, the amounts, if any, due to the accounts of the former ordinary shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made; and thereafter
 - (c) in the third place, the amounts, if any, due to the accounts of the former deferred shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made;
 - (d) after all the amounts mentioned in sub-clauses (a), (b) and (c) above have been paid in full, the surplus, if any, remaining in the hands of the transferee bank shall be distributed *pro rata* among the former ordinary shareholders of the transferor bank :

Provided that if any question arises whether any amounts are due against an account mentioned in any of the above sub-clauses, it shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final :

Provided further that the transferee bank shall give to any person to whom any payment may be due under sub-clauses (a), (b) and (c)

above, such reasonable notice, not exceeding three months and not being less than one month as it may consider appropriate of the payment being due, and

- (a) if during the period of this notice a request has not been received in writing for the payment of the amount due in cash and if the amount of the payment due is also not less than the highest closing price of an ordinary share in the transferee bank as quoted on any recognised stock exchange on or immediately before the date on which the notice is issued, or where the ordinary share of the transferor bank is not quoted on any recognised stock exchange the price of the share as determined by the Reserve Bank, the transferee bank shall allot to the payee a share or shares in the transferee bank to the extent possible and disburse in cash the balance, if any, of the amount which may be due; and

- (b) if the conditions mentioned in sub-clause (a) above are not fulfilled the transferee bank shall disburse the amount in cash:

Provided further that the allotment of the shares or the payments aforesaid shall in each case be made before the end of six months from the date on which notice of the payment falling due is deemed to have been served in accordance with the provisions of this scheme:

- (viii) the amounts due to the collection accounts referred to in this paragraph shall be deemed to be a liability of the transferee bank only to the extent provided for in this scheme;

- (ix) on the expiry of twelve years from the prescribed date or such earlier period as the Central Government after consulting the Reserve Bank of India may specify for this purpose, any item referred to in clause (ii) of this paragraph which may not have been realised by that date shall be valued by the transferee bank in consultation with the Reserve Bank and the transferee bank shall distribute any amount or amounts determined in the light of that valuation after deducting therefrom first any sum necessary for meeting the liabilities referred to in clause (iv) of this paragraph which may remain unsatisfied as on that date in the order and the manner provided in clauses (v), (vi) and (vii) above;

- (x) the transferee bank shall invest such moneys realised on account of items mentioned in the preceding clauses (i), (ii) and (iii) as are not likely to be required by it for immediate payment, in interest bearing deposits with itself or with any other bank or banks, in such manner and for such periods as may be appropriate having regard to the facts and circumstances of the case or as the Reserve Bank of India may direct. The interest accrued shall be applied for meeting the liabilities referred to in clauses (iv), (v), (vi) and (vii) in the manner indicated therein.

(7) For the purposes of allotment to the shareholders of the transferor bank of shares in the transferee bank in terms of the foregoing paragraphs,—

- (i) the transferee bank may issue shares in the manner and to the extent specified in this scheme and thereupon the share capital of the transferee bank shall, notwithstanding the provisions of any enactment, regulation or other instrument, be deemed to have been increased to the extent of the shares which are so issued; or

- (ii) the transferee bank may pay an amount equivalent to the value of the shares which are required to be issued in pursuance of the scheme to the Reserve Bank of India and thereupon in consideration of the amounts so paid, the Reserve Bank of India shall, out of the shares held by it in the transferee bank, transfer shares of an equivalent amount, for and on account of the shareholders of the transferor bank who may be entitled to the allotment of the said shares:

Provided that the Reserve Bank shall not be called upon to transfer shares held by it in the transferee bank, if as a result of the transfer, the shares held by it are reduced to less than fifty five per cent of the issued capital of the transferee bank.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, the allotment of shares under this scheme shall not be made in such a manner that any

person other than the Reserve Bank of India, a Corporation, an insurer as defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), a local authority, a co-operative society or a trustee of a public or private religious or charitable trust, comes to be registered as a shareholder, whether in his own name or jointly with any other person, of more than two hundred shares in the transferee bank; and for securing the above, the number of shares issuable to any person under this scheme, shall, if necessary, be reduced proportionately, payment being made in cash instead of in shares to that extent.

(9) Notwithstanding anything to the contrary contained in any contract, express or implied, no interest shall accrue on account of a deposit or other liability in any account mentioned in paragraphs (5) and (6) after the date of the moratorium except in respect of the staff security deposits mentioned in paragraph (5)(a) and interest shall be paid only in respect of the new accounts opened with the transferee bank in terms of paragraph (5) and credited in accordance with the provisions of that or the next succeeding paragraph and only at such rates as the transferee bank may allow.

(10) No depositor or other creditor of the transferor bank shall be entitled to make any demand against the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent prescribed by this scheme.

(11) No suit or other legal proceedings shall lie against the Central Government, the Reserve Bank of India or the transferee or the transferor bank for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this scheme.

(12) All the employees of the transferor bank other than those specified in the schedule referred to in the succeeding paragraph shall continue in service and be deemed to have been appointed by the transferee bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service as were applicable to such employees immediately before the 10th August, 1969:

Provided that the employees of the transferor bank who have, by notice in writing given to the transferor or the transferee bank at any time before the expiry of one month next following the date on which this scheme has been sanctioned by the Central Government, intimated their intention of not becoming employees of the transferee bank, shall be entitled to the payment of such compensation, if any, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), and such pension, gratuity, provident fund and other retirement benefits as may be ordinarily admissible under the rules or authorisations of the transferor bank immediately before the 10th August, 1969:

Provided further that the transferee bank shall in respect of the employees of the transferor bank who are deemed to have been appointed as employees of the transferee bank be deemed also to have taken over liability for the payment of retrenchment compensation in the event of their being retrenched while in the service of the transferee bank on the basis that their service has been continuous and has not been interrupted by their transfer to the transferee bank.

(13) The persons specified in the Schedule annexed to this scheme shall, on the prescribed date, cease to be the employees of the transferor bank and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any agreement or contract, the persons so specified shall be entitled to and only to such pension, gratuity, provident fund and other retirement benefits as may be ordinarily admissible to them under the rules or authorisations of the transferor bank immediately before the 10th August, 1969.

Provided that the compensation, if any, for the loss of employment, so far as it relates to the unexpired portion of any contract of service, shall be such and only as may be determined by the Reserve Bank (whose determination in this respect shall be final and binding):

Provided further that nothing herein shall be deemed to prevent the transferee bank from re-employing any person whose name has been specified in the schedule annexed to this scheme in such capacity and on such terms and conditions as the transferee bank may deem fit.

(14) The transferee bank shall, on the expiry of a period not longer than three years from the date on which this scheme is sanctioned, pay or grant to

the employees of the transferor bank the same remuneration and the same terms and conditions of service as are applicable to the employees of corresponding rank or status of the transferee bank subject to the qualifications and experience of the said employees of the transferor bank being the same as or equivalent to those of such other employees of the transferee bank :

Provided that if any doubt or difference arises as to whether the qualifications or experience of any of the said employees are the same as or equivalent to the qualifications and experience of the other employees of corresponding rank or status of the transferee bank or as to the procedure or principles to be adopted for the fixation of the pay of the employees in the scales of pay of the transferee bank, the doubt or difference shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final.

(15) The trustees or administrators of any provident fund constituted for the employees of the transferor bank or as the case may be the transferor bank shall on or as soon as possible after the prescribed date transfer to the trustees of the employees provident fund constituted for the transferee bank, or otherwise as the transferee bank may direct, all the money and investments held in trust for the benefit of the employees of the transferor bank :

Provided that such latter trustees shall not be liable for any deficiency in the value of investments, or in respect of any act, neglect, or default done before the prescribed date.

(16) The transferee bank shall submit to the Reserve Bank of India such statements and information as may be required by the Reserve Bank of India from time to time regarding the implementation of this scheme.

(17) The transferee bank shall furnish to the shareholders of the transferor bank a statement of affairs of the transferor bank in such form and at such periodical intervals as the Reserve Bank of India may specify in this behalf. The sending of such statements shall be discontinued when so directed by the Reserve Bank.

(18) Any notice or other communication required to be given by the transferee bank shall be considered to be duly given if addressed and sent by pre-paid ordinary post to the addressee at the address registered in the books of the transferor bank, until a new address is registered in the books of the transferee bank, and such notice shall be done to be served on the expiry of forty-eight hours after it has been posted. Any notice or communication which is of general interest shall be advertised in addition in one or more daily newspapers which may be in circulation at the places where the transferor bank was transacting its business.

(19) If any doubt arises in interpreting any of the provisions of this scheme, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India and its opinion shall be conclusive and binding on both the transferee and transferor banks, and also on all the members, depositors and other creditors and employees of each of these banks and on any other person having any rights or liability in relation to any of these banks.

(20) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this scheme, the Central Government may issue to the transferor and the transferee banks or to either of them such directions not inconsistent with the provisions of this scheme as may appear to the Central Government, after consulting the Reserve Bank of India, to be necessary or appropriate for the purpose of removing the difficulty.

Schedule attached to and forming part of the scheme for the amalgamation of the Bank of Behar Ltd. as sanctioned by the Central Government under sub-section (7) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)

Name of the employee	Designation in the transferor bank
1	2
1. Shri Shri Narayan Singh	General Manager (Chief Executive Officer), Head Office.

1	2
2. Shri Madan Mohan Pandit	Secretary, Head Office.
3. Shri Arbind Lal Mani Lal Gandhi	Chief Accountant, Head Office.
4. Shri Kailash Prasad Sinha	Superintendent of Branches (Establishment), Head Office
5. Shri Surendra Kumar	Inspector of Branches, Head Office.
6. Shri Indra Narain Verma	Manager, Barajamda Branch.
7. Shri Mahadeo Prasad Kapoor	Manager, Kanpur Branch.
8. Shri Sanat Prasad Verma	Manager, Monghyr Branch.
9. Shri Satya Narain Prasad	Officer, Phusro Bazar Branch.

[No. F. 17(10)-BC/69.]

S.O. 4642.—In pursuance of sub-section (7) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby specifies the 8th November, 1969 as the prescribed date in relation to the scheme for the amalgamation of the Bank of Behar Ltd., with the State Bank of India which has been sanctioned by the Central Government under the provisions of the said sub-section.

[No. F. 17(10)-BC/69(I).]

S.O. 4643.—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), and in modification of this Ministry's Notification No. F. 17(10)-BC/69 dated the 8th August, 1969, the Central Government hereby directs that the order of moratorium made by it in respect of the Bank of Behar Ltd., Patna, shall remain in force upto and including the 7th November, 1969.

[No. F. 17(10)-BC/69(ii).]

S.O. 4644.—Whereas a scheme for the amalgamation of the Bank of Behar Ltd., with the State Bank of India has been sanctioned by the Central Government under the said scheme has come into operation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 45 of the Banking Regulation Act 1949, the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank, hereby directs that in its application to the conduct by the State Bank of India of the business acquired by it from the Bank of Behar Limited under section 45 of the said Act, during the period between the 8th November, 1969 and the 7th November, 1976, both days inclusive;—

(1) section 33 of the State Bank of India Act, 1955, shall apply as if:—

(a) clause (i) has been substituted by the following clause namely “(i) the advancing and lending of money and the opening of Cash credits with or without security”; and

(b) in clause (iv), the words “upon any of the securities specified in sub-clauses (a) to (d) of clause (i)” have been omitted, and for the words “for or into any of the other investments above specified” the words “for and into any other investments” have been substituted.

(2) The State Bank shall be exempt from clauses (a) and (c) of sub-section (1) of section 34 and clause (a) and sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (3) of that section, in so far as they preclude the State Bank from—

(i) continuing or realising the loans or advances made for a period longer than twelve months or made against the security of immovable property;

(ii) continuing or realising the loans or advances made against any negotiable instrument which does not carry on it the several responsibilities of at least two persons or firms unconnected with each other in general

partnership or does not mature within twelve months of the date of the loan or advance.

[No. F. 17(10)-BC/69(iv).]

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 4645.—In exercise of the powers conferred by section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act, shall not apply to the Shri Gajanan Sahakari Pedhi Limited, Patan for a period of one year with effect from 1st March, 1969.

[No. F. 18/4/69-SB.]

वित्त मंत्रालय
(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर 1969

एस० नो० 4645.—बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का दसवां) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त, अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबन्ध श्री गजानन सहकारी पेठी लिमिटेड, पाटन पर 1 मार्च, 1969 से लेकर 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 18/4/69-एस० बी०]

S.O. 4646.—In pursuance of the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 6 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (47 of 1961) the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby renominates Shri V. H. Vora, Executive Director, Life Insurance Corporation, Bombay, as a Director of the Deposit Insurance Corporation for a period of two years with effect from the 1st January, 1970.

[No. F. 10/11/69-SB.]

एस० नो० 4646.—जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 (1961 का सैतालीसवां) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से, एतद्वारा जीवन बीमा निगम बम्बई के कार्यकारी निदेशक श्री वी० एच० वोहरा को 1 जनवरी, 1970 से 2 वर्ष की अवधि के लिए फिर से जमा बीमा निगम का निदेशक नामजद करती है।

[सं० एफ० 10/11/69-एस० बी०]

New Delhi, the 11th November 1969

S.O. 4647.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (bi) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), No. F. 18/12/67-SB, dated the 19th March, 1968, published as S.O. 1126 at page 1677 of the Gazette of India-Part II-Section 3-Sub-section (ii) dated the 30th March, 1968.

[No. F. 18/12/67-SB.]

K. YESURATNAM, Under Secy.

नयी दिल्ली, 11 नवम्बर, 1969

एस० नो० 4647:—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का दूसरा) की धारा 2 के खण्ड (ख 1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा अब तक के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) के पृष्ठ 1677 पर सांविधिक आदेश 1126 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय (अर्थविभाग) की 19 मार्च, 1968 की अधिसूचना संख्या एफ० 18/12/67-एस० बी० विखिण्डित की जाती है।

[सं० एफ० 18/12/67 सस बी०]

के० देसुरतम अनु सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 5th November 1969

S.O. 4648.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Council of Scientific and Industrial Research, the "prescribed authority", for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961):—

INSTITUTION

Indian Institute of Science, Bangalore.

[No. 150/F. No. 11/7/69-IT(AII).]

S. N. NAUTIAL, Dy. Secy.

(Department of Revenue and Insurance)

STAMP

New Delhi, the 22nd November 1969

S.O. 4649.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the debentures of the face value of two hundred and fifty lakhs of rupees, to be issued by the Madras State Industrial Development Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 13/69-F. No. 1/40/69-Cus.VII/Stamps.]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

INCOME-TAX

New Delhi, the 6th November 1969

S.O. 4650.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its notification No. 20 (No. F. 55/1/62-IT), dated the 30th April 1963, published as S.O. 1293, on

pages 1454—1457 of the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th May, 1963 as amended from time to time:—

Against Sr. No. 5A, Bombay City-III, under Column 3 of the Schedule appended thereto—

(i) following shall be added:

11. C-V Ward.

12. G-A Ward.

This notification shall take effect from 6th November, 1969.

[No. 151/F. No. 55/403/69-IT(AI).]

L. N. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Bombay, the 30th April 1969

S.O. 4651.—A licence No. P/SS/1553211/C/XX/23/C/8/23-24/SSI dated 8th October, 1966 of the value of Rs. 3826/- for import of Cellulose Nitrate Sheets was issued to M/s. Raja Optical Frames Mfg. Works, Krishna Nagar, Satna, Madhya Pradesh.

2. Thereafter, a show cause notice No. 1/412/67/Enf/5454 dated 13th December, 1967 was issued asking them to show cause within fifteen days as to why the said licence issued in their favour should not be cancelled in terms of Clause 9 sub-clause (cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955 as the unit was reported closed and hence the licence in question was not likely to serve the purpose for which the same had been issued.

3. The aforesaid show cause dated 13th December, 1967 despatched to the firm was returned undelivered from the Postal Authorities.

4. Having regard to what has been stated in the preceeding paragraph, the undersigned is satisfied that the licence in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, in exercise of the powers vested in him under Clause 9 sub-clause (cc) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancels the licence No. P/SS/1553211/C/XX/23/C/8/23-24/SSI dated 8th October, 1966 for Rs. 3826/- issued in favour of M/s. Raja Optical Frames Manufacturing Works, Krishna Nagar, Satna, Madhya Pradesh.

[No. 1/412/67/Enf.]

I. R. KAKAR,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports,
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)
(Central Licensing Area)

ORDER

New Delhi, the 2nd August 1969

S.O. 4652.—Exchange control copy of licence No. P/SS/1610257/C/XX25/C-D/, 25-26 dated 16th March 1968 for Rs. 30,750 for the import of Drugs and Medicines issued in favour of M/s. Pharma Chemico Laboratories, Ramkuti, Circular Road, Solan (H.P.), was cancelled vide order No. 3/Priority-II-H.P./AM.88/AU.HRH/CLA/4398 to 4448 dated 31st March, 1969, as the said firm had reported that the same had been lost/misplaced by them.

The said firm have now reported to this office that the exchange control copy of the said licence has since been traced out. In view of this position, the order

No. 3/Priority-II/HP/AM.68/AU.HRH/CLA/4398 to 4448 dated 31st March, 1969 referred to in para. 1 above is hereby rescinded.

[No. F.3/Priority-II/HP/AM.68/AU.HRH/799.]

S.O. 4653.—M/s. Vinay Plastic and Glass Industries, Railway Road, Bahadurgarh (Har) were granted import licence No. P/S/1611292/C/XX/27/D/25/26 dated 23rd May 1968 for Rs. 5,000 for import of Polythylene Moulding Powder (High Density), Cellulose Acetate Butyrate, Acrylic Plastic Moulding Powder, Polyester film, Cellulose Nitrate Sheets, Rods and Tubes and P/S/1612303/C/XX/29/D/25/26 dated 6th November 1968 for Rs. 5000 for import of A.P. Moulding Powder, Polyester film and C.N. sheets Rods and Tubes. They have applied for issued of duplicate copies of customs purposes and exchange control copies thereof on the ground that the original licences have been lost/misplaced without having been utilised at all.

2. The applicant has filed an affidavit in support of their contention as required under para 302 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure 1969. I am therefore satisfied, that the original Customs Purposes and Exchange Control copies of the licence have been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under section 9 (CC) import (Control) order, 1955, dated 7th December, 1955, I order the cancellation of licence No. P/S/1611292/C/XX/27/D/25/26 dated 23rd May 1968 and P/S/1612303/C/XX/29/D/25/26 dated 6th November 1968..

4. The applicant is now being issued duplicate copies of Customs purposes and exchange control copies of these licences in accordance with the provision of para 302(4) of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure 1969.

[No. F.V-20/HAR/AM.68/AU.HRH/CLA/800.]

S.O. 4654.—M/s. Sunshine General Industries, Railway Road, Bahadurgarh, Distt. Rohtak (Har) were granted an import licence No. P/SS/1610926/C/XX/25/26 dated 17th April 1968 for Rs. 10,000 for the import of Hard Glass Tubings (10 per cent of the face value) Inter changeable Glass Joints (10 per cent of face value), Platinum wire (10 per cent of face value) Electrical Heated flasks (10 per cent of face value) and Silica wares. They have applied for issue of duplicates of Customs Purpose and Exchange control purpose copies thereof on the ground that the original copies have been lost/misplaced.

2. The applicant has filed an affidavit in support of their contention, as required under para 302 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure 1969. I am therefore satisfied that original Custom purpose and Exchange Control copies of the licence in question have been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me, under section 9 (CC) Import (Control) Order, 1955, dated 10th October, 1955, I order the cancellation of the Custom purposes and Exchange Control copies of licence No. P/SS/1610926/C/XX/25/CD/25/26, dated 17th April, 1968.

4. The applicant is now being issued duplicates of Customs purpose as well as exchange control purpose copies of the licence, in accordance with para 302 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure 1969.

[No. F.23/Priority-II/AM.68/HAR/AU.HRH/CLA/801.]

New Delhi, the 3rd October 1969

S.O. 4655.—M/s. United Steel and Allied Industries, B-37, Modern Industrial Estate, Bahadurgarh (Haryana) were granted an import licence No. P/SS/1610299/C/XX/25/CD/25/26 dated 22nd March, 1968 for Rs. 4,000 for the import of P. & M. Tools other than Banned shown against S. No. 21-11 in part-A of the Red Book. They have applied for issue of duplicate copy of the Custom Purposes copy thereof, on the ground that the original has been lost/misplaced without having been registered with any custom authority and utilised at all.

2. The applicant have filed an affidavit in support of the above statement as required under para. 302 of I.T.C. Hand Book 1969. I am satisfied that the custom purpose copy of the licence has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under section 9(cc) Import Control Order, 1955, dated 7th December, 1955, I order the cancellation of the customs purpose copy of import licence No. P/S/1610299 dated 22nd March, 1968.

4. The applicant is now being issued a duplicate copy of customs purpose copy of this licence, in accordance with the provisions of para. 302(4) of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1969.

[No. U-2/HAR/AM.68/AU-HRH/CLA.]

New Delhi, the 15th October 1969

S.O. 4656.—M/s. Panch-Shilla Industries, Opposite Government College, Gurgaon were granted licence No. P/SS/1609215/C/XX/25/CD/23-24 dated 9th January, 1968, for Rs. 17,082 for the import of Tungston Metal Discs, Resistance Wires, Enamelled Copper Wire SWG No. 44,45 and 46 onwards. They have applied for issue of duplicate of Exchange Control copy thereof on the ground that original copy has been lost/misplaced. The licence has been registered with New Delhi Custom house and has been utilised to the extent of Rs. 5,362.

2. The applicant has filed an affidavit in support of their statement as required under para. 302 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1969. I am satisfied that the original Exchange Control copy has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under section 9(cc) Import Control Order, 1955 dated 7th December, 1955, I order the cancellation of Exchange Control copy of import licence No. P/SS/1609215/C/XX/25/CD/23-24 dated 9th January, 1968.

4. The applicant is now being issued a duplicate of the Exchange Control copy of this licence in accordance with the provisions of para. 302(4) of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1969.

[No. F. PN. 84/66/P-105/Har./AM-67/AU. HRH/CLA.]

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 11th September 1969

S.O. 4657.—M/s. Jon's Footwear Co., 14 Kachery Road, Boilueganj, Agra were granted import licence No. P/AU/1211966/C dated 28th March 1968 for Rs. 6609. They have applied for duplicate Customs Purposes Copy of the licence on the ground that the original Customs Purposes Copy thereof has been misplaced without having been registered with any customs authorities and without having been utilised at all.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purposes Copy of the licence No. P/AU/1211966/C dated 28th March 1968 has been misplaced and direct that duplicate Customs Purposes Copy of the licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy of the licence is Cancelled.

[No. Leather-11/JM.67/SC.III/CLA.]

RAM MURTI SHARMA,
Joint Chief Controller of Imports and Exports.

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Panjim Goa, the 7th October 1969

S.O. 4658.—M/s. Venktesh Shenai Phonsule, Ferces Road, Santa Cruz—Goa were granted import licence No. P/E/0138842 C/XX/28/G/27-28, dated 19th July, 1968 on G. A. for the Import of MILK POWERED AND CONDENSED/INCLUDING MILK FOOD FOR INFANTS/valued at Rs. 1,000 under S. No. 9-10-IV. They have requested for issue of duplicate Exchange Control copy of the licence on the ground that the original Exchange Control Copy of the licence has been lost. It has further been reported by the party that the licence lost was partly utilised for Rs. 351 and leaving a balance of Rs. 649. The licence was registered with Marmagao Customs.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit on a stamped paper duly attested by Taluka Magistrate, First Class, Panjim, Goa. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control Copy of the licence No. P/E/0139842/C/XX/28/G/27-28, dated 19th July, 1968 has been lost and direct that duplicate Exchange Control Copy of the said licence should be issued to them.

In exercise of the powers conferred on me under Section 9 (cc) of Import Control Order, 1955 dated 7th December 1955, I order the cancellation of Exchange Control Copy of the licence No. P/E/0139842/C/XX/28/G/27-28, dated 19th July 1968.

The applicant is now being issued a duplicate copy of Exchange Purpose Copy of this licence in accordance with the provisions contained in para 302 (1) of ITC Hand Book of Rules and Procedure, 1969.

[No. EI/9-10-IV/2/AM69.]

R. D. PAWAR,

Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Calcutta, the 10th November 1969

S.O. 4659.—A licence No. P/S/1631628/C/XX/30/C/27-28/AU-V dated 19th March, 1969 of the value of Rs. 900 for import of safety Lamp excluding Electric Safety Torches was issued to M/s. Mine Safety Appliances Ltd., 240A, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta-20.

Thereafter, a show cause notice No. 186/69/E&L dated 8th October, 1969, was issued asking them to show cause within 15 days as to why the said licence in their favour should not be cancelled on the ground that the goods are indigenously available in terms of Clause 9, Sub-Clause (a).

3. No response to the aforesaid show cause notice had been received from M/s. Mine Safety Appliances Ltd., 240A, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta-20.

4. Having regard to what has been stated in the preceeding paragraph, the undersigned is satisfied that the licence in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, in exercise of the powers vested in him under Clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the licence No. P/S/1631628/C/XX/30/C/27-28/AU-V dated 19th March, 1969, for Rs. 900 issued in favour of M/s. Mine Safety Appliances Ltd., 240A, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta-20.

[No. 186/69/E&L.]

M. S. PURI,

Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 13th November 1969

S.O. 4660.—M/s. Kwaliti Restaurant, Bombay were granted an import licence No. PA/1288396/C/XX/26/C/H/2526 dated 15th January, 1968, for Rs. 500 (Rupees five hundred only) for the import of Chinese Delicacies viz., Gourmet Powder, Dried Mushrooms and Shark's Fin. They have applied for the issue of a duplicate Customs purpose copy of the said licence on the ground that the original Customs purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the licence (Customs purpose copy) was not registered with any Customs Authority at the Ports, and was not utilized at all.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am accordingly satisfied that the original customs purpose copy of the said licence has been lost/misplaced. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(CC) of Imports (Control) Order 1955, dated 7th December, 1955, as

amended, the said Customs purpose copy of the said licence No. P/A/1288396/C/XX/26/C/H/25-26 dated 15th January, 1968, issued to M/s. Kwaliti Restaurant, Bombay is being cancelled.

A duplicate Customs purpose copy of the said licence is being issued to the licensee separately.

[No. 14/1012/1/AM-68/ILS/2494.]

G. D. BAHL,

Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 6th November 1969

S.O. 4661.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby declares that the provisions of the said Act shall apply to the following article, namely:—

Soyabean

[No. F. 13.26/69-LA.]

B. R. KAPOOR, Under Secy.

जाय, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर 1969

का० आ० 4661.—कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिह्न) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित वस्तु को लागू होंगे, अर्थात्:—

सोयाबीन

[सं० एफ० 13-26/69-एल० ए०]

बी० आर० कपूर, अवर सचिव ।

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नयी दिल्ली, 8 सितम्बर 1969

का० आ० 3767 :—राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड स्थापित करती है

जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा और श्री एम० बी० कृष्णप्पा को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नामनिर्देशित करती है,

अर्थात्:

1. श्री एम० बी० कृष्णप्पा	}	संसद द्वारा निर्वाचित
2. श्री सी० सी० देसाई		
3. श्री हरि कृष्ण		
4. श्री कामेश्वर सिंह		
5. श्री मुल्का गोविन्द रेड्डी		
6. श्री बाई० आदिनारायण रेड्डी		
7. श्री के० बी० लाल	}	केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि
8. श्री एस० के० दत्त		
9. श्री सी० पी० श्रीवास्तव		
10. श्री पी० एन० जैन		
11. रियर एडमिरल एन० कृष्णन		
12. श्री के० सी० मदप्पा		
13. श्री ए० रामास्वामी महालियर	}	गोतस्वामियों के प्रतिनिधि
14. श्रीमती सुमति मोरारजी		
15. श्री एन० एच० थुनजीमोई		
16. श्री जे० डी० रेथरी	}	नाविकों के प्रतिनिधि
17. श्री असित मित्र		
18. श्री के० के० खादिलकर		
19. श्री जी० एम० पारिख	}	अन्य हितों के
20. श्री एल० एन० बिरला		
21. श्री एच० एम० त्रिवेदी		

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन० के० गोपालन नायर, (पोत परिवहन) उप महानिदेशक को बोर्ड का सचिव नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 37-एम०डी० (6)/69]

जसवंत सिंह, अव्वर सचिव ।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 4662.—In exercise of the powers conferred by Section 72 of the Indian Patents and Designs Act, 1911 (2 of 1911), the Central Government hereby appoints the Deputy Chief Engineer, Technical Services, Bharat Heavy Electricals Limited, Heavy Electricals Equipment Plant, Hardwar, U.P. as an authority for the purpose of the said section, and makes the following further amendment in the notification

of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O. 681, dated the 23rd March, 1955, namely:—

In the said notification, after item 35 and the entry relating thereto, the following item and entry shall be added, namely:—

- (36) "Deputy" Chief Engineer, Technical Services, Bharat Heavy Electrical Limited, Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar U.P."

[No. 33(42)-PP&D/69.]

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर 1969

एस० ओ० 4662.—भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन अधिनियम, 1911 (1911 का 2) की धारा 72 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उप-मुख्य इन्जीनियर टेक्निकल सर्विसेज, भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लि०, हेवी इलेक्ट्रीकल्स इक्विपमेंट प्लान्ट हरिद्वार, उ० प्र० को उपरिलिखित धारा के प्रयोजन का प्राधिकारी नियुक्त करती है तथा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० 681, दिनांक 23 मार्च, 1955, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात्:—

उपरिलिखित अधिसूचना में मद 35 तथा उस से सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

- (36) उप-मुख्य इन्जीनियर,
टेक्निकल सर्विसेज, भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लि०,
हेवी इलेक्ट्रीकल इक्विपमेंट प्लान्ट,
हरिद्वार, उ० प्र० ।

[संख्या 33 (42)-पी० पी० एण्ड डी०/69]]

S.O. 4663.—In exercise of the powers conferred by Section 72 of the Indian Patents and Designs Act, 1911 (2 of 1911), the Central Government hereby appoints the Director of Industries and Supplies, Rajasthan, Jaipur, as an authority for the said section, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O. 681, dated the 23rd March, 1955, namely:—

In the said notification, after item (37) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely:—

- "(38) The Director of Industries and Supplies, Jaipur, Rajasthan".

[No. F. 33(43)-PP&D/69.]

एस० ओ० 4663.—भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन अधिनियम, 1911 (1911 का 2) की धारा 72 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेशक उद्योग तथा संभरण, राजस्थान, जयपुर को उपरिलिखित धारा का प्राधिकारी नियुक्त करती है तथा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 681, दिनांक 23 मार्च, 1955, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात्:—

उपरिलिखित अधिसूचना में, मद (37) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि निविष्ट की जाएगी, अर्थात्:—

- "(38) निदेशक, उद्योग तथा संभरण, जयपुर, राजस्थान ।"

[सं० 33(43)-पी० पी० एण्ड डी०/69]

S.O. 4664.—In exercise of the powers conferred by Section 72 of the Indian Patents and Designs Act, 1911 (2 of 1911), the Central Government hereby appoints the Joint General Manager, Heavy Machine Building Plant, Heavy Engineering Corporation Limited, Dhurwa, Ranchi, Bihar, as an authority for the purpose of the said Section, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O. 681, dated the 23rd March, 1955, namely:—

In the said notification, after item (36) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be added, namely:—

“(37) The Joint General Manager, Heavy Machine Building Plant, Heavy Engineering Corporation Limited, Dhurwa, Ranchi, Bihar”.

[No. F. 33(44)-PP&D/69.]
HARGUNDAS, Under Secy.

एस० आ० 4664.—भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन अधिनियम, 1911 (1911 का 2) की धारा 72 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा संयुक्त महाप्रबन्धक, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लान्ट, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, धुर्वा, रांची, बिहार को उपरिलिखित धारा के प्रयोजन का प्राधिकारी नियुक्त करती है तथा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० आ० 681, दिनांक 23 मार्च, 1955 में निम्नलिखित श्रौत आगे संशोधन करती है, अर्थात्:

उपरिलिखित अधिसूचना में मद सं० (36) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(37) संयुक्त महाप्रबन्धक,
हैवी मशीन बिल्डिंग प्लान्ट, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० धुर्वा, रांची, बिहार ।”

[सं० एक० 33(44)-पी० पी० एण्ड डी०/69]

हरगुनदास, अवर सचिव ।

(Department of Internal Trade)

New Delhi, the 12th November 1969

S.O. 4665.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 675, dated the 25th April, 1959 as amended by notification No. S.O. 1269, dated the 1st June, 1959.

[No. 10(9)-IT/69.]
P. SITARAMAN, Dy. Secy.

(अन्तर्वेशीय व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर 1969

का० आ० 4665.—प्रथिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1269, तारीख 1 जून, 1959 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सं० का० आ० 675, तारीख 25 अप्रैल, 1959 को एतद्वारा विखण्डित करती है ।

[सं० 10(9)-आई० टी०/69]

प० सीतारामन, उप सचिव ।

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 6th November 1969

S.O. 4666/IDRA/6/4/69.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years with effect from the date of this Order, the following persons to be members of the Development Council for the scheduled industries engaged in the manufacture or production of Inorganic Chemicals, in place of members appointed under the Government of India, late Ministry of Industry Order No. S.O. /IDRA/6/2/66 dated the 12th December, 1966, as amended from time to time, whose term of office has expired by efflux of time or otherwise:—

Development Council for Inorganic Chemical Industries

1. Shri Charat Ram, M/s. Delhi Cloth and General Mills Limited, Bara Hindu Rao, Delhi—Chairman.
2. Shri D. S. Seth, Director-in-charge, Tata Chemicals Limited, Bombay.
3. Dr. D. N. Daruwalla, Divisional Manager, M/s. Larsen and Toubro Limited, Ballard Estate, Bombay.
4. Dr. B. V. Bhoota, M/s. Dorr Oliver India Limited, 15, Queen's Road, Estate, Bombay-1.
5. Shri D. R. Morarji, M/s. Dharamsi Morarji Chemical Corporation Limited, Bombay-1.
6. Shri P. C. Jain, M/s. Dhrangadhra Chemical Limited, Bombay.
7. Dr. S. K. Mukherjee, Fertilizer Corporation of India, Bombay.
8. Shri S. S. Kanoria, Kanoria Chemicals Limited, Calcutta-1.
9. Shri P. K. Sen, C/o. M/s. A. V. B. Limited, Durgapur-6 (West Bengal).
10. Shri R. V. Ramani, Managing Director, Mettur Chemical and Industrial Corporation Limited, Mettur Dam, R. S. (Tamil Nadu).
11. Shri J. Simon, M/s. E. I. D. Parry Limited, Madras.
12. Shri M. M. Gurunath, Salt Consultant, 3, Lakshmana Chetty Street, Madras.
13. Shri S. K. Vakil, M/s. Saurashtra Chemicals Limited, Porbandar (Gujarat).
14. Shri B. R. Kamdar, M/s. Digvijay Salt Works, Jamnagar.
15. Shri T. V. Srivastava, Managing Director, Gujarat State Fertilizer Corporation, Baroda.
16. Shri B. B. Ramiah, Joint Managing Director (Tech.), Andhra Sugar Limited, Tanuku (A. P.).
17. Dr. K. S. Chari, Director, Technical Institute, Fertilizer Association of India, 85, Sundar Nagar, New Delhi.
18. Shri Paul Pothan, Managing Director, Indian Farmer Fertilizer Corporation Limited, New Delhi.
19. Shri M. K. K. Nair, Managing Director, M/s. Fertilizer and Chemical Travancore Limited, Alwaye.
20. Shri D. G. Rao, Fertilizer Corporation of India Limited; P & D Division, Sindri.
21. Shri J. D. Adhya, Managing Director, Hindustan Zinc Limited, Zinc Smelter, Debari (Udaipur).
22. Shri B. Ramachandran, Director, State Trading Corporation of India, New Delhi.
23. Dr. K. N. Syngal, Soil and Fertilizer Specialist, Ministry of F. A. C. D. and C., (Department of Agriculture), New Delhi.
24. Shri M. N. Kale, Deputy Secretary, Ministry of P. & C. and M. M. (Deptt. of Chemicals), New Delhi.
25. Shri K. L. Gambhir, Salt Commissioner, (Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs), Jaipur.

26. Shri K. Venkataraman, Deputy Secretary, Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, (Department of Industrial Development), New Delhi.

27. Shri P. K. Seshan, Industrial Adviser (Chemicals), D.G.T.D., New Delhi.

2. Shri P. K. Seshan, Industrial Adviser (Chemicals), D.G.T.D., New Delhi, is hereby appointed to carry on the functions of the Secretary to the said Development Council.

[No. 13(15)/68-L.C.]

R. C. SETHI, Under Secy.

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 11th November 1969

S.O. 4667/IDRA/18G/69.—In exercise of the powers conferred by section 18G and section 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely:—

1. (1) This Order may be called the Cement Control (Third Amendment) Order, 1969.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Cement Control Order, 1967, after item No. 1 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“1A. Assam Cements, Cherrapunji 123.50”

[No. 1-33/68-Cem.]

G. RAMANATHAN, Under Secy.

(Department of Industrial Development)

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 3rd November 1969

S. O. 4668.—In pursuance of sub-regulation (4) of Regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations, 1955 as amended from time to time the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the licence, particulars of which are given below, has been cancelled with effect from 1 November, 1969 :

Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licence	Relevant Indian Standard
CM/L-464 24-10-1962	M/s. Geo Industries & Insecticides (India) Pvr. Ltd., Field No. 82/3(a) Sathankadu, kaladipet, Madras-19.	BHC Water Dispersible Powder Concentrates.	IS : 562—1958

[No. CMD/55: 464.]

New Delhi, the 15th November 1969

S. O. 4669.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standard Institutions Certification marks Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. CM/L-2006, particulars of which are given below, has been cancelled with effect from 25th Sept. 1969 at the request of the firm :

Licence No. & Date	Name and address of the licensee	Article/Process covered by the licence cancelled	Relevant Indian Standard
CM/L-2006 30-6-1969	M/s. Shriram Vinyl & Chemical Industries, Shriramnagar, Kota-4 (Rajasthan).	Rigid Plain P.V. C. Conduits for Elec- trical Installations Outer Dia 25 mm	IS : 2509-1963 Spec- ification for Rigid Non-Metallic Con- duits for Electrical Installations.

[No. MDD/55:2006.]

(DR). A. K. GUPTA,
Deputy Director General (Marts)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 4th November 1969

S.O. 4670.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-rule (3) of rule 8 read with sub-rule 2 of rule 9 of Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby re-appoints Smt. R. Shamanta as a member of the Advisory Panel of the Central Board of Film Censors at Madras with immediate effect upto 31st December, 1969.

[No. 11/10/69--F(C).]

New Delhi, the 5th November 1969

S.O. 4671.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-rule (3) of rule 8 read with sub-rule 2 of rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby appoints Shri Bhogilal Chimanlal Shah after consultation with Central Board of Film Censors as a member of the Advisory Panel of the said Board at Bombay with immediate effect, upto 31st December, 1969.

[No. 11/12/69-F(C).]

VIRENDRA D. VYAS, Dy. Secy,

ORDERS

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 4672.—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

- (1) Sub-Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).
- (2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).
- (3) Sub-Section (4) of Section 5 and Section 9 of the Saurashtra Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Saurashtra Act XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	The Giver and The Taker.	609·60M	Sh. Prakash Arora, Director of Arora Films, Arora Hospital, Khar, Bombay-52.	Director of Information, Govt. of Gujarat Ahmedabad	Documentary film (for release in Gujarat Circuit only).
2	Mahitichitra Number 113.	249·94M	Director of Information, Government of Gujarat, Ahmedabad.	Sachivalaya, Ahmedabad.	Film dealing with news and current events (for release in Gujarat circuit only).

[No. F. 24/1/69-FP.App.1400.]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर 1969

एस० ओ० 4672:—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके गुजराती भाषा के रूपान्तर सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उप-धारा (4) तथा धारा 16 ।
- (2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उप-धारा (3) तथा धारा 9 ।
- (3) सौराष्ट्र सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां) सौराष्ट्र अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) तथा धारा 9 ।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1	दि गिवर एण्ड दि टेकर	609.60 मीटर	श्री श्रीम प्रकाश अरोड़ा, अरोड़ा फिल्मज, अरोड़ा हस्पाताल, खार, बम्बई-52	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, अहमदाबाद	डाकुमेन्ट्री फिल्म (गुजरात सर्किट में रिलीज करने के लिये)
2	महिचित्रा संख्या 113	249.94 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, सचिवालय, अहमदाबाद		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात सर्किट में रिलीज करने के लिये)।

[संख्या फा० 241169-एफ० पी० परिशिष्ट 1400)

S.O. 4673.—In pursuance of the directions issued under the provision of the enactment specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Hindi to be of the description specified against it in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of Section 5 of Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (Uttar Pradesh Act No. 3 of 1956).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	Uttarakhand (Hindi)	355.00	Sh. Dharendra Pande, Films Officer, Dtc. of Information Govt. of U.P., Lucknow	Director of Information, Govt. of U.P. Lucknow	Documentary film, (for release in U.P. circuit only).

एस० ओ० 4673 इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म की उसके हिन्दी भाषा के रूपांतर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1955 (1956 की तीसरी उत्तर प्रदेश अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4) ।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मि०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकु-मैट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1	उत्तराखंड (हिन्दी)	355.00 मीटर	श्री धीरेन्द्र पांडे, फिल्म अधिकारी, सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	डाकुमैट्री फिल्म (केवल उत्तर प्रदेश सर्किट के लिये)

[संख्या० फा० 24/1/69—एफ० पी० परिशिष्ट 1401]

S.O. 4674.—In pursuance of the directions issued under the provision of the enactment specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Telugu to be of the description specified against it in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (3) of Section 5 of the Andhra Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (President's Act 4 of 1955).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	Milk Milk Milk (Telugu)	336.19M	Shri B.R. Sathyan, R.S. Movics, 3/145 Hyterbasti, Secunderabad, Andhra Pradesh		Documentary film (for release in the Telugu speaking areas)

[No. F. 24/1/69-FP.App.1402.]

K. K. KHAN, Under Secy.

एस० ओ० 4674 . इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अर्न्तगत जारी किये गये निदेशनों के अनुसार, केन्द्रीय, सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म की उसके तेलगु भाषा रूपान्तर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

- (1) आन्ध्र प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1955 (1955 का राष्ट्रपति का अधिनियम 4) की धारा 5 की उप-धारा 3.

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकमेन्ट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	मिल्क, मीटर	मिल्क, मिल्क 336.19	श्री बी० आर० सथ्यान, आर. एस. मवीज, 3/145, हतरबस्ती सिकन्द्राबाद, आन्ध्र प्रदेश	डाकमेन्ट्री फिल्म (केवल आन्ध्र प्रदेश सर्किट के लिये)	

[संख्या फा० 24/1/69 एफ० पी०—परिशिष्ट 1402]

के० के० खान, अवर सचिव ।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING
AND URBAN DEVELOPMENT**

(Department of Health)

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 5675.—In exercise of the powers conferred by section 8A of the Aircraft Act, 1934, (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Indian Aircraft (Public Health) Rules, 1954, the same having been previously published as required by section 14 of the said Act, namely :—

1. These rules may be called the Indian Aircraft (Public Health) Amendment Rules, 1969.

2. In the Indian Aircraft (Public Health) Rules, 1954;

(i) In rule 1, the word "Indian" shall be omitted;

(ii) In rule 48, for the words "the District Magistrate for the place of death", the words "the District Magistrate or the Deputy Commissioner or the Chief Presidency Magistrate or the Coroner within whose jurisdiction the death took place" shall be substituted.

[No. 34-1/64-I.H.]

S. SRINIVASAN, Under Secy.

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 4676.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-5/62-MI, dated the 23rd July, 1962, the Central Government has directed that the Medical qualification "M.D." awarded by the University of Georgetown, Washington, U.S.A. shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956);

And, whereas, Dr. (Miss) Eileen Niedfield who possesses the said qualification is for the time being attached to the Holy Family Hospital, Mandar, Ranchi District for the purposes of charitable work in the country;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies :—

(i) a period upto the 31st December, 1969 or

(ii) the period during which Dr. (Miss) Eileen Niedfield is attached to the said Holy Family Hospital, Mandar, Ranchi District,

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. F. 19-6/68-MPT.]

R. MURTHI, Under Secy.

(Department of Works Housing and Urban Development)

New Delhi, the 15th November 1969

S.O. 4677.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958 (32 of 1958), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the table below, being officer of the Bokaro Steel Limited equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in Column (2) of the said table.

THE TABLE

Designation of officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Town Administrator Bokaro Steel Limited Bokaro Steel City, District Dhanbadli Bihar.	Premises belonging to and under the administrative control of Bokaro Steel Limited which have been acquired by the State of Bihar for Bokaro Steel out of portion of Chas Police Station and the portion of Hazaribagh District which has been transferred to Dhanbad District.

[No. F. 21011(4)/66-Pol.IV.]

T. K. BALASUBRAMANIAM,

Dy. & Director of Estates and
Ex-Officio Under Secy.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 12th November 1969

S.O. 4678—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Posts and Telegraphs Inspectors of Mail Motor Service and Head Clerks of Mail Motor Service Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Indian Posts and Telegraphs Inspectors of Mail Motor Service and Head Clerks of Mail Motor Service Recruitment (Amendment) Rules, 1969;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Posts and Telegraphs Inspectors of Mail Motor Service and Head Clerks of Mail Motor Service Recruitment Rules, 1967, in the entries in columns 7 and 10, for the figure and word "1st January" the figure and word "1st July" shall be substituted.

[No. 5/53/69-SPB. II.]

R. RAJAGOPALAN,
Assistant Director General (SPN).

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 4679.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 3), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kharkharee Colliery of Messrs Bharat Mining Corporation Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd November, 1969.

THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 3)
AT DHANBAD

REFERENCE No. 8 of 1969

PRESENT:—

Shri Sachidanand Sinha, M.A.M.L., Presiding Officer:

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Kharkharee Colliery.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For employers: Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For workmen: Shri S. N. Mishra, General Secretary.

INDUSTRY: Coal

STATE: Bihar.

Dhanbad, the 27th of October 1969

AWARD

1. The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kharkharee colliery of Messrs Bharat Mining Corporation Limited, Post Office Kharkharee, District Dhanbad and their workmen, by its order No. 2/240/68-LRII dated the 18th of January, 1969 referred under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 to this Tribunal for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the Schedule annexed thereto. The Schedule is extracted below:—

SCHEDULE

- "1. Whether the action of the management of Kharkharee Colliery of Messrs Bharat Mining Corporation Limited Post Office Kharkharee, District Dhanbad in transferring Sarvashri Shiwaji Singh, Nand Kishore Singh, Samad Seikh and Jadu Mahato, Mining Sirdars to the Dakra Bukhuka Colliery owned by Messrs United Karanpura Collieries Limited with effect from the 7th August, 1968 was justified?
2. If not, to what relief are the workmen concerned entitled?
3. Whether the refusal of the management to pay wages to the four workmen, Sarvashri Shiwaji Singh, Nand Kishore Singh, Samad Seikh and Jadu Mahato, Mining Sirdars for the period of their idleness from the 7th August, 1968 to the 12th October, 1968 (Both days inclusive) was justified?
4. If not, to what relief are the workmen entitled?
5. Whether the action of the management in refusing employment to Shri Shyam Narayan Jadav, Mining Sirdar with effect from the 7th August, 1968 was justified?
6. If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The Director, Kharkharee Colliery, Bharat Mining Corporation Ltd. filed written statement on 20th March, 1969 Shri S. N. Mishra, General Secretary, Kharkharee Ganeshpur Labour Union filed written statement on behalf of the workmen on 4th June, 1969. It is unnecessary to state the respective cases of the parties because the dispute has now been settled amicably. They have filed a compromise petition duly verified by the Director, Kharkharee colliery, Bharat Mining Corporation Ltd. on behalf of the employer and by Sri S. N. Mishra, General Secretary, Kharkharee Ganeshpur Labour Union on behalf of the workmen. According to the terms of compromise the concerned workmen S/Shri Shiwaji Singh, Nand Kishore Singh, Samad Seikh, Jadu Mahato and Shyam Narayan Jadav have since joined Kharkharee Colliery and the period from 7th August, 1968 till they are joining will be treated as if they were on leave for the purpose of their continuity of service only. The concerned workmen S/Shri Shiwaji Singh, Samad Seikh and Jadu Mahato will be paid 30 (Thirty) days wages each as an *Ex-gratia* payment for the period from 7th August, 1968 to their respective dates of joining service. S/Shri Nand Kishore Singh and Shyam Narayan Jadav will be paid each 45 (Forty five) days wages as an *Ex-gratia* Payment for the period from 7th August, 1968 till their respective dates of joining service. The concerned workmen S/Shri Shiwaji

Singh, Samad Seikh, Jadu Mahato and Nand Kishore Singh and Shyam Narain Jadav will be treated as if present in their duties in the period of their idleness for the purpose of service continuity and they will get all other facilities (Leave, Bonus etc.) linked with the attendance and the aforesaid amount will be paid within 15 days of this settlement. The terms are fair and satisfactory and the same are accepted.

3. Let the reference be disposed of in terms of the compromise Annexure "A" which will form part of the award. The award now be submitted to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) SACHIDANAND SINHA
Presiding Officer.

ANNEXURE "A"

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3 DHANBAD.

REFERENCE No. 8 OF 1969

PARTIES:—Employers in relation to the Management of Kharkharee Colliery of M/s Bharat Mining Corporation Ltd.

AND

Their Workmen.

The parties above named beg to submit that without prejudice to their respective contentions contained in the written statement the present dispute has been amicably settled between the parties on the following terms:—

1. That S/Shri Shiwaji Singh, Nand Kishore Singh, Samad Seikh, Jadu Mahato and Shyam Narain Jadav have since joined Kharkharee Colliery and the period from 7th August, 1968 till they are joining will be treated as if they were on leave for the purpose of their continuity of Service only.

2. That S/Shri Shiwaji Singh, Samad Seikh and Jadu Mahato will be paid 30 (Thirty) days' wages each as an *Ex-gratia* payment for the period from 7th August, 1968 to their respective dates of joining service.

3. That S/Shri Nand Kishore Singh and Shyam Narain Jadav will be paid each 45 (Forty Five) days wages as an *Ex-gratia* payment for the period from 7th August, 1968 till their respective dates of joining service.

4. That S/Shri Shiwaji Singh, Samad Seikh, Jadu Mahato and Nand Kishore Singh and Shyam Narain Jadav will be treated as present in their duties in the period of their idleness for the purpose of service continuity and they will get all other facilities (Leave, Bonus etc.) linked with the attendance.

5. That the above payment will be paid within 15 days of this settlement.

6. That the above terms of settlement finally resolves all the disputes pending between the parties.

7. That the parties will bear their respective costs of this proceeding.

It is, therefore, prayed that this settlement may kindly be recorded and an Award passed in terms thereof.

For Workmen.
(Sd.) Illegible
The General Secretary,
Kharkharee Ganeshpur
Labour Union.
P.O. Maheshpur.
Distt. Dhanbad.

For Employer
(Sd.) Illegible
Director
Kharkharee Colliery.
Bharat Mining Corporation Limited.

S.O. 4680.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Jhagrakhand Colliery, Post Office Jhagrakhand Colliery, District Surguja (Madhya Pradesh), and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st November, 1969.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT, JABALPUR**

Dated October 24, 1969

PRESENT:—

Shri G. C. Agarwala, Presiding Officer.

CASE No. CGIT/LC(R)(34) OF 1969

PARTIES:

Employers in relation to the management of North Jhagrakhand Colliery, Post Office Jhagrakhand Colliery District Surguja (M.P.)

Vs.

Their workmen represented through the Azad Koyala Shramik Sabha, Jhagrakhand Colliery, Distt. Surguja (M.P.).

APPEARANCES:

For employers—Shri G. R. Bhandari, Group Personnel Officer, Jhagrakhand Collieries.

For workmen—Shri Abhiman Singh President, Azad Koyala Shramik Sabha Jhagrakhand Colliery.

INDUSTRY: Coal Mine

DISTRICT: Surguja (M.P.).

AWARD

By Notification No. 5/14/69/LRII dated 21st August, 1969, the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), Government of India, referred the following matter of dispute as stated in the schedule to the order of reference to this Tribunal, for adjudication:

Matter of Dispute

“Whether keeping in view of the recommendations of the Wage Board in Appendix VI at page, 54, Volume II of the Central Wage Board for Coal Mining Industry the demand of the Azad Koyala Shramik Sabha, Post Office Jhagrakhand Colliery for placing Shri K. N. Pandey, Clerk Grade III as Grade II in North Jhagrakhand Colliery, is justified? If so, to what relief is the workman entitled?”

2. The dispute relates to the fitment of a workman, Sri K. N. Pandey, Clerk who had been placed in Grade III. The demand of the workman and the Union, however, was that he should be fitted in Grade II in consequence of Central Wage Board recommendations. Before, however, statements of claim could be filed parties compromise the dispute and a petition of compromise settlement which has been verified before me was filed on 23rd October 1969 and is annexure to the award. The Union agreed to the position that Sri K. N. Pandey has been correctly placed in Clerical Grade III. At the same time, the management agreed to give him Grade II in recognition to his past services with a basic salary of Rs. 226/- per month with effect from 1st November, 1969. The dispute is thus satisfactorily resolved. An award in terms of compromise petition is hereby recorded.

(Sd.) G. C. AGARWALA,
Presiding Officer.
24-10-1969.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, JABALPUR

In the matter of Reference No. CGIT/LC/(R)(34) of 1969

PARTIES: Employers in relation to North Jhagrakhand Colliery of M/s Jhagrakhand Collieries Pvt. Ltd., P.O. Jhagrakhand Colliery, Distt: Surguja (M.P.):

Vs.

Their Workmen

The joint petition on behalf of the employers and the workmen most respectfully sheweth:

1. That the parties have settled the above dispute on the following terms:

- (a) The union accepts that considering the nature of work performed by Sri K. N. Pandey Clerk, Noth Jhagrakhand Colliery he has been correctly placed in Clerical Grade III.
- (b) The management in recognition of the past service of Sri Pandey, agrees to put him in clerical grade II with starting basic salary of Rs. 226/- per month with effect from 1st November, 1969.
- (c) The union agrees that Sri K. N. Pandey shall work in any job falling under clerical Grade II as may be assigned by the management from time to time.
- (d) The workman has no other claim whatsoever against the management.
- (e) The parties will bear their own cost of the proceedings.

2. The parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to give its award in the present Reference in the aforesaid terms.

Signed at Jhagrakhand Colliery on the 18th day of October, 1969.

Representing Workmen
(Sd.) ABHIMAN SINGH

Representing Employers
(Sd.) G. R. BHANDARI

President,
Azad Koyla Shramik Sabha,
Jhagrakhand Colliery.
(Sd.) B. BORAL
18-10-1969.

18-10-1969.
Group Personnel Officer,
Jhagrakhand Collieries.
(Sd.) G. R. BHANDAR

General Secretary,
Azad Koyala Shramik Sabha,
Jhagrakhand Colliery,
Dated 18th October, 1969

Verified
(Sd.) G. C. AGARWALA
23-10-1969.

(Sd.) B. BORAL
23-10-1969.

Part of Award

(Sd.) G. C. AGARWALA,
Presiding Officer.
24-10-1969.

[No. 5/14/69-I.R.II.]

New Delhi, the 13th November 1969

S.O. 4681.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of Shri K. Sharan, Arbitrator, Asansol, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ranipur Colliery of Messrs Equitable Coal Company Limited, Post Office Dishergarh, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st October, 1969.

BEFORE SHRI K. SHARAN, REGIONAL LABOUR COMMISSIONER(C),
ASANSOL

AND

Arbitrator

PRESENT:—

Shri K. Sharan, Regional Labour Commissioner(C), Asansol.

PARTIES:

Employers in relation to Ranipur Colliery of M/s. Equitable Coal Company Limited, P.O. Dishergarh, District Burdwan.

Vrs.

Their workmen represented by the Colliery Mazdoor Sabha (A.I.T.U.C.), P.O. Raniganj, District Burdwan.

APPEARANCES:

For employer—Lt. Col. S. P. Sharma, Chief Personnel Officer, M/s. Equitable Coal Co. Ltd.

For the workmen—Shri Robin Chatterjee, Vice-President Colliery Mazdoor Sabha (AITUC), P.O. Raniganj, Burdwan.

INDUSTRY: Coal Mine

DISTT: Burdwan (West Bengal).

No. E. 1/1(6)/69.

Asansol, the 27th October, 1969

AWARD

The Central Government, having received on the 24th September, 1969, a written agreement dated the 3rd September, 1969, between the employers in relation to Ranipur Colliery of M/s. Equitable Coal Co. Ltd., P.O. Dishergarh, Dist. Burdwan (hereinafter referred to as the management) and their workmen represented by the Colliery Mazdoor Sabha (AITUC), P.O. Raniganj, Dist. Burdwan (hereinafter referred to as the Union) in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referring the industrial dispute between them, the specific matters in dispute being detailed below, to my arbitration and the Central Government being of the opinion that the industrial dispute referred to above existed between the said management and their workmen, ordered publication of the said arbitration agreement in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) under its order No. 6/68/69-LRII dated the 13th October, 1969:

Specific matters in dispute

"Whether the management of Ranipur Colliery of M/s. Equitable Coal Company Limited was justified in transferring the workmen named below from Ranipur Colliery to different collieries/establishments mentioned against the name of the respective workman? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

Sl. No.	Name of the workmen	Designation	Date of order of transfer	Transferred to
1	2	3	4	5
1.	Shri Banwari	Timber Mistry	21-6-69	Bejdih Colliery.
2.	Shri Kali Roy	Machine Driver	23-7-69	Bejdih Colliery.
3.	Shri Sashnath Pandey	U/G. Trammer	23-7-69	Methani Colliery.
4.	Shri Bhagbat Chatterjee	Electrician	23-7-69	Methani Colliery.
5.	Shri Gour Hari Roy	W.O's Clerk	23-7-69	Agent's Office at Methani"

2. The representative of the management submitted to me a written statement dated 8th September 1969 which was received by me on 12th September 1969. The representative of the union did not submit any written statement. The parties were called upon to attend hearing at my office on 9th September 1969 but the hearing could not take place as the parties did not submit their written statement in this regard. However, the hearing was finally adjourned to be held at my office on 15th September 1969 on which date Shri Lt. Col. S. P. Sharma, Chief Personnel Officer appeared on behalf of the management and Shri Robin Chatterjee, Vice-President, Colliery Mazdoor Sabha (AITUC), Raniganj appeared on behalf of the workmen. On 15th September 1969 the parties filed a joint petition of compromise dated 12th September 1969 stating therein that the dispute was amicably settled between the parties on the terms incorporated in the joint petition of compromise dated 12th September 1969 and that I might accept the terms of the settlement incorporated in the joint petition of compromise referred to above and pass my award accordingly. The terms of the settlement incorporated in the joint petition of compromise dated 12th September 1969 were duly verified and brought on record. The terms of the settlement, incorporated in the joint petition of compromise referred to above appear to me to be fair, reasonable and in the interest of the workmen concerned and as such I accept them. Accordingly, I make my arbitration award in terms of the joint petition of compromise dated 12th September 1969 and submit it to the Central Government under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947. The joint petition of compromise in question is annexed hereto and made part of the award.

Sd./- K. SHARAN,
Regional Labour Commissioner(C),
Asansol & Arbitrator.

**BEFORE THE ARBITRATOR SHRI K. SHARAN, REGIONAL LABOUR
COMMISSIONER (CENTRAL), ASANSOL**

In the matter of Industrial dispute between the management of Ranipur Colliery of M/s. Equitable Coal Co. Ltd., P. O. Dishergarh, Distt. Burdwan.

AND

Their workmen represented by the Colliery Mazdoor Sabha (AITUC), P.O. Raniganj, Distt. Burdwan.

The parties hereby jointly submit that the dispute in question has been amicably resolved by them on the following terms:—

- (1) The transfer orders issued by the management of Ranipur Colliery to S/Shri Banwari and Gour Hari shall be withdrawn by the management and they would be posted back to Ranipur Colliery with effect from 15th October, 1969.
- (2) Shri Kali Roy who has already joined at Bejdih Colliery as per his transfer order shall also be ordered to join back at Ranipur Colliery within 7 days from date.
- (3) The union agrees not to press the case of other two workmen involved in this dispute namely S/Shri Sashnath Pandey and Bhagbat Chatterjee who have already carried out the transfer orders.
- (4) The management further agrees that the period of absence of the three workmen namely S/Shri Banwari, Gour Hari and Kali Roy after the servicing of the transfer orders to them shall be treated as leave without pay.

(5) The Arbitrator may therefore, be pleased to award accordingly.

Representing the employers

Representing the Employees.

Sd/- Lt. Col. S. P. Sharma (Retired)
Chief Personnel Officer,
M/s. Equitable Coal Co. Ltd.,
P. O. Dishergarh, Distt. Burdwan.
dated September 12, 1969.

Sd/- ROBIN CHATTERJEE, Vice President,
Colliery Mazdoor Sabha, P.O. Raniganj,
Burdwan.

S.O. 4682.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Datla West Colliery of the Amalgamated Coalfields Limited, Post Office Parasia, District Chhindwara (M.P.), and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st November, 1969.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT JABALPUR**

Dated October 27, 1969

PRESENT :

Shri G. C. Agarwala,—Presiding Officer.

CASE No. CGIT/LC(R)(20) of 1969

PARTIES :

Employers in relation to the management of Datla West Colliery of the Amalgamated Coalfields Ltd., P.O. Parasia, District Chhindwara (M.P.).

Vs.

Their workmen represented through the Satpura Koyala Khadan Mazdoor Congress, P.O. Junnardeo, District.—Chhindwara (M.P.).

APPEARANCES :

For employers—Shri S. D. Singh, Personnel Officer, The Amalgamated Coalfields Ltd., The Pench Valley Coal Co. Ltd.

For workmen—Shri Ramnarayan Singh, General Secretary Satpura Koyala Khadan Mazdoor Congress.

INDUSTRY : Coal Mine

DISTRICT : Chhindwara (M.P.).

AWARD

By Notification No. 5/24/68-LRII dated 14th April, 1969, the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Department of Labour and Employment), Government of India, referred the following matter of dispute as stated in the schedule to the order of reference to this Tribunal, for adjudication:

Matter of dispute

Whether the management of the Datla West Collieries of Messers Shaw Wallace and Company Limited, Post Office Parasia, District Chhindwara, Madhya Pradesh, was justified in categorising the workmen named below as dressers and paying an allowance of 25 paise per shift per worker for performing the duties of dresser in addition to their duties as dressers?

1. Kandha	T. No.	1816
2. Kanhai	T. No.	1031
3. Rahman	T. No.	1831
4. Bhikha	1060
5. Surat Singh	9096
6. Premchand	1012
7. Mahadeo	1806
8. Chandidas	1823
9. Ramcharan	1811
10. Mahip Singh	1025
11. Purvec	1828
12. Maharaj Singh	1027
13. Raghunath	1055
14. Rameshwar	1827
15. Mahboob	1824
16. Gandlal	1022
17. Chandrika	1826
18. Dashrath	1835
19. Bhabutia	1813
20. Bhondal	1018
21. Gulabchand	T. No.	1843
22. Langru	"	1822
23. Jotia	"	1043

24. Ganpati	T. No.	1808
25. Bhura	"	1809
26. Kartik	"	1024
27. Malikadas	"	1029
28. Rusma	"	1788
29. Ilamesbagul	"	1028
30. Seonath	"	1292
31. Samaru	"	1030
32. Nandlal	"	1934
33. Sekhauram	"	1820
34. Buddhu	"	1830
35. Tantu	"	1067
36. Tamman
37. Ojha
38. Lalau
39. Bahadur
40. Ratan
41. Sekh Sakoor

If not, to what relief are the workmen entitled?

After pleadings were filed certain issues were framed on 10th July, 1969. Before, however, evidence could be recorded, parties on this date of hearing compromised the dispute and filed a compromise petition which was duly verified before me and is annexure to the award. From the terms of the compromise petition, it appears that the management has agreed to give category IV and designate 4 workmen namely Channidas, Mahip Singh, Maharaj Singh and Rehman as Drillers. For others, the parties agreed that as they have been working for a short time only as Drillers the allowance of Rs. 0.25 paise shall be raised to Rs. 0.37 paise. The dispute is thus satisfactory resolved and an award in terms of compromise petition which is accepted is hereby recorded.

Sd./- G. C. AGARWALA,
Presiding Officer.
27-10-69.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT (CENTRAL) JABALPUR

IN THE MATTER OF REFERENCE No. CGIT/LC(R) (20)/69

PARTIES:

Employers in relation to Datla West Colliery of the Amalgamated Coal fields Ltd., P.O. Parasia, Dist. Chhindwara (M.P.)—*Non-Applicants*.

Vs.

Their workmen of Datla West Colliery, represented by the Satpura Koyala Khadan Mazdoor Congress, P.O. Junnordeo, Distt. Chhindwara (M.P.)—*Applicants*.

Both the above mentioned parties jointly submit as under:

1. That the above reference was made by the Government of India, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Dept. of Labour & Employment) to this Hon'ble Tribunal under their Order No. S.O. 5/24/68-LRII dated 14th April, 1969, which is now fixed for hearing for 27th October, 1969.

2. That M/s. Shaw Wallace & Co. Ltd. have ceased to be the managing agents of the Amalgamated Coalfields Ltd. with effect from 15th August 1969, and as such, the employers of the workers under Terms of Reference are M/s. The Amalgamated Coalfields Ltd., P.O. Parasia, Dist. Chhindwara (M.P.), and not M/s. Shaw Wallace & Co. Ltd., as mentioned in the terms of Reference.

3. That both the parties have now mutually settled this dispute among themselves on the following terms:

Terms of Settlement

1. That it is agreed that all the Dressers and all the Drillers of Datla West Colliery have been doing the combined job of dressing and drilling within 8 hours

of their shift duty for the last 10 years and they will continue to do so in future. However, during major part of their shift, Dressers do the job of dressing of coal roof, etc. and for a shortwhile, as and when required, they do the job of drilling for which at present they are being paid 25 P per Dressers per shift. But, the dressers at the other mines of M/s. The Amalgamated Coalfields Ltd. & The Pench Valley Coal Co. Ltd., are doing the job of dressing-cum-drilling for the past many years, for which they are paid adequate drilling allowance, to which the union agrees and has no objection to such existing system of work.

2. Both the parties agree that the Dressers have been correctly put in Cat. III of the Coal Wage Board Recommendations and during their major part of their shift they do the job of dressing. However, to resolve the dispute and to have better industrial relations, both the parties agree that the 25 P allowance as mentioned in para 1 above, will be increased to 37 p (thirty seven paise only) per Dresser per shift for doing the combined job of dressing and drilling within their 8 hours of shift, within two weeks from the date of filing of this settlement and the Dressers will not be entitled for any arrears on this account.

3. Both the parties agree that the following Dressers will be designated as Drillers in Category IV of the Central Wage Board Recommendations, i.e. Rs. 6.90-8.90 on basic of Rs. 7.10 per day, within a week from the date of filing of this mutual settlement before this Hon'ble Tribunal:

1. Shri Channidas, Dresser.
2. Shri Mahip Singh, Dresser.
3. Shri Maharaj Singh, Dresser.
4. Shri Rehman, Dresser.

4. Both the parties agree that in case of any promotion of any workman to the post of Dresser or Driller, he shall do the combined job of dressing and drilling as per terms hereinabove.

5. That the Union agrees that it shall not raise any further dispute nor prefer any claim in future in this regard. Both the parties state that the dispute under reference pending before this Hon'ble Tribunal, thus stands finally settled and resolved. The parties shall bear their own cost.

Prayer

Both the parties pray that an Award may kindly be passed in terms of the aforesaid Settlement.

Applicants

(Sd.) RAMNARAYAN SINGH
General Secretary,
Satpura Koyala Khadan Mazdoor
Congress, P.O. Junnordeo, Dist.
Chhindwara (M.P.).

Non-Applicants

(Sd.) S. D. SINGH
Personnel Officer,
The Amalgamated Coalfields Ltd. The
Pench Valley Coal Co. Ltd., P.O.
Parasia, Distt. Chhindwara (M.P.).
Verified.

(Sd.) G. C. AGARWALA,
Presiding Officer.

Dated October 25, 1969.

Part/ of the Award

(Sd.) G. C. AGARWALA,
Presiding Officer.

27-10-69

[No. 5/24/68-LRII.]

S.O. 4683.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of P. D. Kajora Colliery, Post Office Kajoramgram, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st November, 1969.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

REFERENCE NO. 57 OF 1969

PARTIES:

Employers in relation to the management of P. D. Kajora Colliery

AND

Their workmen.

PRESENT:

Shri B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Absent.

On behalf of Workmen—Shri B. S. Azad, General Secretary, Khan Mazdoor Congress.

STATE: West Bengal

INDUSTRY: Coal Mines

AWARD

By Order No. 6/28/69-LRII, dated July 22, 1969, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following dispute between the employers in relation to the management of P. D. Kajora Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the management of P. D. Kajora Colliery Post Office Kajoragram, District Burdwan was justified in terminating the service of Shri Bineshwar Singh with effect from the 28th November, 1968 and if not, to what relief the workman is entitled?"

2. The workmen filed a belated written statement after I had sent a notice for fixation of a date of peremptory hearing. The employer behaved in their usual non-cooperative way. They did not file their written statement, did not appear before this Tribunal on the date fixed for settlement of a date of hearing and also did not appear on the date fixed for peremptory hearing. In Reference No. 35 of 1969, between the same parties, in which I passed an award on August 13, 1969, I had to observe:

"The employer colliery adopted an attitude of strange non-cooperation with the Tribunal from the beginning. It did not file written statement in time. After the date had arrived for settlement of peremptory date of hearing, the management woke up and wrote a letter asking for time to file written statement on the following ground:

"In view of the absence of the dealing clerk to attend for knowing the date and time to be fixed by your Honour for hearing the above Reference No. 35 of 1969 case, which may kindly be directed to your office to intimate me by letter, further more, I beg to state that replies of the W. S. of above reference is not yet ready, due to our Legal Adviser is out of station, so further 3 weeks time is solicited."

Apart from the clumsiness of the language used, the ground pleaded is flimsy. Even then this Tribunal fixed the peremptory date of hearing for July 31, 1969, with liberty to the management to file their written statement before that date. Two days prior to the date of peremptory hearing, the management filed a written statement but did not care to appear on the date of peremptory hearing. All that it did was to send an unworn and unverified application asking for adjournment of the peremptory hearing on the ground of manager's illness."

This time the management exhibited worse non-cooperation. It did not wake up at all and led thinks to drift for themselves. It is no use postponing the case excepting that the management would wake up, which they will never do. I therefore take up the case for *ex parte* hearing.

3. It appears from the evidence of the workman himself that he was a permanent workman entitled to get Provident fund, Bonus and also Railway fare for going home. Bonus cards were exhibited and marked Exts. 1, 2 and 3. Prior to the date of his termination of service, he was working for 6 or 7 years in the colliery.

Suddenly the order of termination of service, dated November 28, 1968 (Ext. 4), was sent to the workman couched in the following language:

"As your work is unsatisfactory, the management is hereby terminating your service from the date of this letter.

Please collect your dues if any and vacate the quarters."

The workman protested to the Manager by his letter dated November 28, 1968. He also wrote a letter, dated December 2, 1962, in the following language (Ext. 5):

"With reference to your above letter I beg to state that I am working in your above colliery since long permanently and regularly with the full satisfaction of my Superiors. So the question of that your work is unsatisfactory does not arise at all. Further the contention of your above letter that you are Probationer U/G Trammer is totally false and baseless. I am working regularly and permanently since long. So this type of wrongful and illegal termination notice is quite illegal, unfair and unjust natural justice.

Further I am active member of the Khan Shramik Congress union and protested several times against your illegal activities regarding short and under payment, thus you became displeased and unnecessarily issued me this illegal and wrongful termination letter without any reason. This termination notice was never offered me by Peon Book in any day, hence this allegation is also false.

So you are requested to consider the matter and please try to reinstate me on my original job with immediate effect with the full back wages for the above illegal stoppage period and oblige."

Standing Orders of the employer company provide:

"3(b) A 'permanent' workman is one who is appointed for an unlimited period or who has satisfactorily put in three months' continuous service in a permanent post as a probationer."

Here, on the evidence I find that the workman was working for more than 6 or 7 years. Even if in the Bonus Card he had at first been described as a probationer, he had put in more than 3 months' continuous service thereafter and he must be deemed to have become a permanent workman.

4. It appears from the letter of termination of service (Ext. 4) that the service of the workman was terminated for blameworthiness. Now, the service of a permanent workman cannot be terminated in such a high-handed fashion without a chargesheet, without an enquiry, without a report, and without proof of blameworthiness. I, therefore, hold that the termination of service was unlawful.

5. In the view that I take, I set aside the order termination of service and direct reinstatement of the workman with full back wages from the date of termination of service. Liberty is reserved to the employer to terminate the service of the workman afresh according to Rule.

This is my award.

Dated, October 22, 1969.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.
[No 6/28/69-LRII.]

New Delhi, the 14th November 1969

S.O. 4684.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khas Dharmaband Colliery of Messrs Khas Dharmaband Colliery Company (Private) Limited Post Office Malkera District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd November, 1969.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

REFERENCE NO. 34 OF 1968

PARTIES:

Employers in relation to the Khas Dharmaband Colliery of Messrs Khas Dharmaband Colliery Company (P) Ltd., P. O. Malkera. Distt. Dhanbad.

AND

Their Workman.

PRESENT:

Shri Kamla Sahai, Presiding Officer,

APPEARANCES:

For the Employers: Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For the Workman: Shri S. K. Mukherjee, Advocate.

STATE: Bihar

INDUSTRY: Coal.

Camp: Bombay, the 29th October, 1969

AWARD

By order No. 2/45/68-LR II, dated the 7th May, 1968, the Central Government, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) has made this reference to this Tribunal for adjudication of a dispute which has been described in the schedule attached to the reference as follows:—

SCHEDULE

Whether the action of the management of Khas Dharmaband Colliery of Messrs Khas Dharmaband Colliery Company (P) Ltd., Post Office Malkera, District Dhanbad in dismissing Shri Nabin Chandra J. Mehta, Accountant/Cashier with effect from the 21st August, 1967 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The management's case is that payment to workers had to be made on Saturday the 1st July, 1967, but, owing to the fact that there was delay in receipt of the money, payment started rather late and the entire payment could not be concluded on that date. According to the usual practice, payment had to start again early in the morning on Monday the 3rd July, 1967. Shri Nabin Chandra J. Mehta, Accountant/Cashier came that morning to the colliery office at about 8-30 A.M. instead of 7 A.M. when work usually starts. The Manager, Shri M. H. A. Mallick, sent for him and he came to the Manager's office. At that time, a number of workers had assembled at the door of the Manager's office and thereabouts and were making a row. The Manager asked Shri Nabin Chandra J. Mehta, the alleged delinquent, why he was getting him (the Manager) insulted and asked him to hand over charge of the cash to Shri Magan Bhai (Magan Lal N. Shethia). Nabin Chandra J. Mehta refused and left the office. The Manager then sent a slip to him, instructing him in writing to hand over charge of the cash to Shri Magan Lal N. Shethia but he refused again, saying that he would not hand over charge of the cash until he received instructions from Sri R. N. Singh, Director, or from Calcutta.

3. The management's case further is that, at about 10-45 A.M. on the same date, Sri Mehta sent a slip to the Manager asking for his permission to go to Jharia to get his wound dressed. The Manager replied verbally that he was giving him a written reply within about ten minutes. Before this, Shri Mehta had asked the Manager to hand over the duplicate key of the Iron Safe but the Manager had replied "I am not able to give the key as you are not ready to hand over the cash to Shri M. N. Shethia".

4. Shri Mehta handed over a written report (Ext. 14) in which he stated *inter alia* that he had begun payment on Saturday at about 4-15 P.M. and that he had got the pay counter closed at 6-45 P.M. because the Manager had previously

asked him in the morning to come to him at about 7-00 P.M., for discussion relating to books of accounts, that hulla was made by workers and labour leaders to continue payment, that having failed to contact the Manager on phone, he (Shri Mehta) went to the Manager's house and met him at about 7-00 P.M.; that the Manager asked him to continue payment until 9-00 P.M. and to come to him on Sunday but, when Shri Mehta told him that the discussions would take more than three hours, the Manager asked him to come for the discussions on Monday, that Shri Mehta started payment again and continued payment until about 9-10 P.M., that he left the colliery at about 8-00 A.M. on Sunday the 2nd July along with his family, that he was gheraoed by some wagon loaders between Dharmaband and Mohuda at a place near Amjharna and told him that the Manager wanted him back and that, if he (Mehta) did not go back, they would not allow him to proceed further. Mehta then asked the loaders to ask the Manager to send him a conveyance, for he could not go back on foot to the colliery which was at a great distance. The loaders further told Mehta that the Labour Welfare Officer (Shri B. P. Yadav) had instructed them to gherao him. Subsequently the loaders did not bring a conveyance for Mehta and thereafter Mehta was allowed to proceed to his father-in-law's house where he was going.

5. The Manager kept the above report with himself. Later, on the same date, the Manager drew up chargesheet No. KD/CS/24/875/67 against Mehta. In that chargesheet, Shri Mehta was alleged to have committed the following misconduct:—

- (1) Of wilful in subordination, disobedience of the lawful and reasonable order of the superior under clause 1 of clause 27 of the certified standing orders and
- (2) of leaving work without permission under clause 27(18) of the certified standing orders.

6. Pending enquiry, Shri Mehta was called upon to hand over charge of the colliery cash by physical counting to Shri M. N. Shethia. General Supervisor as he had already been directed to do.

7. Mehta gave a reply to the chargesheet on the 5th July, 1967, denying the charges. Notice of enquiry (Ex. M-2) was served on the 6th July. The domestic enquiry was held by Shri S. R. P. Singh Group Labour Officer, on the 15th, 21st and 27th July, 1967. The proceedings of the enquiry are Ext. M-3. On the 3rd August, the enquiring officer submitted his report (Ext. M-6). I may shortly summarise what he has stated therein. He has given eight points and has pointed out the evidence which proves those points. He has mentioned that the management examined four witnesses before him namely Shri B. P. Yadav (P.W. 1), Labour Officer, Shri M. N. Shethia (P.W. 2), General Supervisor, Shri Duryodhan Dasandhi (P.W. 3), Office Peon and Shri M. H. A. Mallick (P.W. 4), Manager of Khas Dharmaband Colliery. The enquiring officer has also pointed out the witnesses who have supported the different points formulated by him and he has further added that item Nos. 3, 4, 5 and 7 were admitted by Shri Mehta himself in the statement which he made before the enquiring officer. He also referred to the facts which Shri Mehta contradicted and has shown that his contradictions cannot be correct. He has then given the conclusion that both the charges framed against Shri Mehta have been established and he is guilty. Before giving his conclusion, he has stated that Shri Mehta fully cross-examined the company's witnesses who were examined against him and that he was also given full opportunity to adduce defence evidence and to make his own statement. Ext. M-7 is a letter dated the 9th August, 1967 sent by the Director of the colliery to the Manager, giving permission to him to dismiss Shri Mehta from service.

8. Ext. M-8 is letter No. KD/24/1846/67 dated 10th August, 1967 sent by the Manager to Shri Mehta. He has conveyed orders by this letter that Shri Mehta would stand dismissed from service with effect from the 21st August, 1967. He further offered Shri Mehta one month's wages as required by section 33(2) of the Industrial Disputes Act.

9. Shri S. K. Mukherjee, Advocate, who has appeared on behalf of the alleged delinquent, has argued only three points. His first point is that Shri Mehta has been victimised. No proof has at all been offered by or on behalf of Shri Mehta to prove this allegation nor has any suggestion to that effect been accepted by any of the management's witnesses. This point, therefore, fails.

10. The second point which Shri S. K. Mukherjee has argued is that the enquiry report is perverse. I have carefully gone through the enquiry report as well as

the entire evidence and I have formed the opinion that the report is well-reasoned, and perfectly sound.

11. Shri S. K. Mukherjee has pointed out that, by a letter (Ext. W-10), Shri Mehta asked the Manager to make over to him one of the duplicate keys in order to enable him to make over charge. I do not quite see the importance of this letter because it is the admitted case of both parties that Shri Mehta did make over charge to Shri Shethia ultimately at about 3-15 P.M. in compliance with the Manager's orders given in writing on the stationery of Khas Dharmaband Colliery. It is also the admitted case of Shri Mehta that he did not make over charge of the cash to Shri Shethia in compliance with the oral order or the written order of the Manager, given on a slip of paper. That clearly makes out the first charge against Shri Mehta. I cannot accept the stand of Shri Mehta as correct if his stand is, as is apparent, that illegality and validity are attached to the Manager's orders only when he puts them down in writing and that too when he puts down his orders on the stationery of the colliery. Ext. W-9 is the order in writing on the stationery of the colliery by the Manager to Shri Mehta and he himself seems to have made an endorsement that he received it at 3-15 P.M. The same letter contains an endorsement by the Manager that he had requested the cashier earlier by a written order on a slip to hand over charge of the cash.

12. The third point which Shri S. K. Mukherjee has raised is that the Manager's case in his evidence before the Tribunal is different from what it was in his evidence before the enquiring officer. Shri M. H. A. Mallick was examined before the Tribunal as M.W. 1. At one stage in his evidence, he wished to give the entire story in brief. He then gave the time when Shri Mehta came to the colliery as having been 9-30 A.M. though the companies' case before the enquiring officer was that he came to the colliery at about 8-30 A.M. I do not attach any importance to this time because Shri Mallick may have mentioned a wrong time before the Tribunal on account of failure of memory. His evidence before the Tribunal also differs from his previous evidence about the timing when he sent an oral message to Shri Mehta to hand over charge to M. N. Shethia. He, however, says before the Tribunal also that Shri Mehta refused to accept the oral message and, therefore, he (the Manager) sent him a chit to the same effect. In these circumstances, I do not think that the Manager has made any material change in his evidence.

13. The evidence shows clearly that, because Shri Mehta asked in writing for permission to leave the colliery the Manager stated to him that he would give his reply also in writing. I do not think that the Manager was wrong in saying that he would give his reply in writing. Admittedly, Mehta went away from the colliery before he got written permission from the Manager to leave it. That being so, there can be no doubt that the second charge has also been established. In any case, I find that the enquiry has been held legally and properly. There was no infringement of natural justice at the enquiry. As I have already said, the conclusions of the enquiring officer are not perverse. In these circumstances, it is not open to me to interfere. Reference made in this connection to the Supreme Court's decision *Mills Company, Limited versus its workmen and another*, reported in 1963 (II) L.L.J. 78.

14. For the reasons given above, I have come to the conclusion that the action of the management of Khas Dharmaband Colliery in dismissing Shri Nabin Chandra J. Mehta, Accountant Cashier with effect from the 21st August, 1967 was completely justified. He is, therefore, not entitled to any relief.

15. This is my award. Let it be submitted to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act.

Sd./- KAMLA SAHAI,
Presiding Officer.
[No. 2/45/68-LRII.]

ORDERS

New Delhi, the 6th November 1969

S.O. 4685.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bhowra Colliery of Messrs Karam Chand Thapar and Brothers, Post Office Bhowra, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, (No. 3), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whereas the demand of the Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad, for fixation of the grade of Sarvashri Deb Das Banerjee and Yogendra Prasad Singh, Lamp Room Incharge, Bhowra Colliery of Messrs Karam Chand Thapar and Brothers, Post Office Bhowra, District Dhanbad, in Grade I with effect from the 15th August, 1967 as recommended by the Central Wage Board for Coal Mining Industry is justified? If so, to what relief are the workmen entitled?"

[No. 2/60/69-LR. II]

S.O. 4686.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jaipur Udyog Limited, Phalodi Quarry, Sawalmadhapur, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Gopal Narain Sharma Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refer the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the employer in treating the following workmen as "Casual", even after several years of continuous service, is justified. If not, to what relief are the workmen entitled?

Sl. No.	Name	Father's Name	Designation	Date from which working
1	2	3	4	5
1	Shrimati Ramdei	Mohanlal	Kuli.	7-1-1964
2	" Dhanni	Dema.	Sweeper	1-9-1964
3	Shri Goverdhan	Natholi	"	1-10-1964
4	Shri Ramdas	Nathulal	"	"
5	Shri Bihari	Madho.	"	1-9-1964
6	Shri Dharampal	Petbahadur.	Beldar.	12-5-1964
7	Shri Prabhudayal	Ram Dayal.	"	21-11-1964
8	Shri Ramu	Kaisa.	"	16-6-1964
9	Shri Chhotesingh	Kalyan Singh.	"	26-5-1964
10	Shri Shanker.	Mooliya.	"	26-5-1964
11	Shri Jagdish Singh	Ladu Singh	"	24-12-1964
12	Shri Murli	Jaliya	"	19-2-1965
13	Shri Nand Singh	Chhitar Singh	"	12-2-1964
14	Shri Hanumansingh	Magan Singh	"	12-2-1964
15	Shri Raghunathsingh	Bhanwar Singh	"	5-12-1964
16	Shri Moti	Baldev	Beldar	11-5-1964
17	Shri Ram Nath.	Soniya	"	20-11-1964
18	Shri Harjidevi Ram	—	"	12-5-1964
19	Shri Virendrasingh	Chhitar Singh	"	15-11-1964
20	Shri Bhunewar Singh	Mithu Singh	"	15-3-1965
21	Shri Prabhu	Chhitar	"	26-5-1964
22	Shri Ummesingh	Chhitar Singh	"	11-5-1964

1	2	3	4	5
23	Shri Sohanlal	Gordhan	Beldar	26-11-1964
24	Shri Amar Nath	Moolraj	"	1-5-1965
25	Shri Har Narain	Sunder	"	22-9-1964
26	Shri Shiv Charan	Kanhaya Lal	"	19-2-1965
27	Shri Dwarkaprasad	Bengali Gupta	"	19-2-1965
28	Shri Moti	Hardev	"	26-5-1964
29	Shri Preetamsingh	Buta Singh	"	26-5-1964
30	Shri Mangu	Chhoga	"	11-5-1964
31	Shri Kaman	Yusuf	"	26-5-1964
32	Shri Hira	Shri Lal	"	26-5-1964
33	Shri Kishanlal	Hajari	"	26-5-1964
34	Shri Ganesh	Manfool	"	27-3-1965
35	Shri Jiva	Prema	"	4-6-1964
36	Shri Juvara	Dharma	"	4-6-1964
37	Shri Hira	Derga	"	26-5-1964
38	Shri Puran	Chhoga	Khanwar	4-11-1964
39	Shri Kanhaya	Goru	Gadiwan	16-4-1965
40	Shri Hira	Chania	Beldar	11-5-1964
41	Shri Dunga	Maiyan	"	11-5-1964
42	Shri Ram Niwas	Panchu	"	12-5-1964
43	Shri Keshra	Harji	"	11-5-1964
44	Shri Tejpal	Chhoga	"	13-6-1964
45	Shri Hajari	Ganga Ram	"	11-5-1964
46	Shri Kanhaya	Onkar	"	12-5-1964
47	Shri Kajor	Vishniya	"	11-5-1964
48	Shri Ramswarup	Gulji	"	9-7-1964
49	Shri Prabhu	Ramhet	"	11-5-1964
50	Shri Gangaram	Ram Pal	"	11-5-1964
51	Shri Moolya	Radhakishan	"	11-5-1964
52	Shri Ramswarup	Laxmi Narain	"	26-9-1964
53	Shri Jaganth	Bhanwar Lal	"	11-5-1964
54	Shri Laddu	Koriyan	"	12-5-1964
55	Shri Ramkalyan	Kanwarlal	"	26-5-1964
56	Shri Pokhar	Hajari	"	26-6-1964
57	Shri Bhanwarlal	Kishanlal	"	12-5-1964
58	Shri Bajranga	Onkar	"	26-5-1964
59	Shri Shobha	Tulsa	"	26-6-1964
60	Shri Kalyan	Jiwan	"	12-5-1964
61	Shri Keshra	Ghasi	"	11-5-1964
62	Shri Hajari	Soniya	"	11-5-1964
63	Shri Ramchandra	Bhura	"	11-5-1964
64	Shri Bansi	Hajari	"	11-5-1964
65	Shri Bhanwarlal	Hiralal	"	26-5-1964
66	Shri Chuniya	Dilipa	"	16-6-1964
67	Shri Kalyan	Bhura	"	16-6-1964
68	Shri Bajran a	Kujiya	"	26-5-1964
69	Shri Gordhan	Bajranga	"	26-5-1964
70	Shri Ram Nath	Narain	"	26-5-1964
71	Shri Nanga	Onkar	"	11-5-1964
72	Shri Goru	Kani Ram	"	11-5-1964
73	Shri Jai Ram	Bhairon	"	26-5-1964
74	Shri Ram Phool	Sukh Lal	"	11-5-1964
75	Shri Srikishan	Sundra	"	16-6-1964
76	Shri Ghisa	Mukundiya	"	16-6-1964
77	Shri Bajranga	Raghunath	"	16-6-1964
78	Shri Ramhet	Goriya	"	12-6-1964
79	Shri Mangal	Jai Kishan	"	13-6-1964
80	Shri Harchand	Kana	"	16-6-1964
81	Shri Ram Kumar	Kawanriya	"	26-5-1964
82	Shri Ganesh	Arjun	"	11-6-1964
83	Shri Moolchand	Lakma	"	16-11-1964
84	Shri Bhajan	Kajor	"	12-5-1964
85	Shri Balka	Praga	"	25-6-1964
86	Shri Tilak Singh	Sukh Ram	"	16-6-1964
87	Shri Balu	Bargha	"	26-5-1964
88	Shri Gulab singh	Bansi Singh	"	26-5-1964

1	2	3	4	5
89	Shri Mehila	Ghurisingh	Beldar	26-5-1964
90	Shri Suraj Bhansingh	Kesharsingh	"	26-5-1964
91	Shri Moti	Chandra	"	26-5-1964
92	Shri Hajari	Dhanna	"	11-5-1964
93	Shri Mohan	Kumpa	"	26-5-1964
94	Shri Kana	Ramnath	"	26-5-1964
95	Shri Mukandsingh	Sultan Singh	"	26-5-1964
96	Shri Chhitar	Kishan Lal	"	26-5-1964
97	Shri Jagdish	Shivji	"	19-9-1964
98	Shri Hira	Moolya	"	5-11-1964
99	Shri Laxman	Onkar	"	12-5-1964
100	Shri Gokal	Harphool	"	26-5-1964
101	Shri Ramniwas	Bhairoon	"	26-5-1964
102	Shri Teja	Onkar	"	26-5-1964
103	Shri Magiya	Sukha	"	26-5-1964
104	Shri Devilal	Mangilal	"	12-5-1964
105	Shri Kalyan	Devchand	"	12-5-1964
106	Shri Gokul	Bhoora	"	22-9-1964
107	Shri Kalu	Kishna	"	11-5-1964
108	Shri Kanyan	Mangilal	"	12-5-1964
109	Shri Hatiya	Ravta	"	4-6-1964
110	Shri Suwa	Mewaram	"	3-11-1964
111	Shri Madansingh	Samundrasingh	"	11-5-1964
112	Shri Goverdhan	Kalla	"	19-2-1965
113	Shri Kishna	Pooniya	"	21-9-1964
114	Shri Ramniwas	Kana	"	12-5-1964
115	Shri Subhashchandra	Ladda Ram	"	26-5-1964
116	Shri Shanker	Bhura	"	26-5-1964
117	Shri Hajari	Moolya	"	19-3-1965
118	Shri Ram Lal	Moolya	"	19-9-1964
119	Shri Sukhji	Moolya	"	22-9-1964
120	Shri Jagannath singh	Onkarsingh	"	10-11-1964
121	Shri Ladu	Goriya	"	19-2-1965
122	Shri Hira	Gangaram	"	19-2-1965
123	Shri Foolya	Goriya	"	19-2-1965
124	Shri Sriram	Dhanna	"	19-2-1965
125	Shri Raja Ram	Jagnath	"	19-2-1965
126	Shri Nanga	Handu	"	12-5-1964
127	Shri Dhanna Lal	Laxmi Narain	"	21-9-1961

[No. 36/32/69-LRIV]

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 4687.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudium Collieries (Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Mohammad Najmuddin, as Presiding Officer with headquarters at Afzal Lodge, Tilak Road, Ramkote, Hyderabad-1, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Having regard to the nature of duties performed, the emoluments drawn and status enjoyed by Sarvashri Maka Venkanna, Jallu Bhushanam, Jithugu Venkanna, Rayadu Suranna and Nakka Suranna, Ex-Supervisors of the Andhra Labour Force, how far the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudium is justified in allotting to them the monthly grade of Rs. 165—230 under the recommendations of Central Wage Board for Coal Mining Industry. If not, to what relief are these workers entitled and from what date?"

[No. 7/11/69-LRIL]

S.O. 4688.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Gondudih Colliery of Messrs Central Alkusa Colliery Company, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 3) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Gondudih Colliery of Messrs Central Alkusa Colliery Company, Post Office Kusunda, District Dhanbad, in rendering idle Shri Achyutanand Mishra, Store-Keeper-Magazine Incharge, with effect from the 2nd May, 1968 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. 2/25/69-LR.II.]

New Delhi, the 12th November 1969

S.O. 4689.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Duduwala and Company (Private) Limited, Mica Mine Owners, Bhilwara, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Gopal Narain Sharma as Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the resignation tendered by Shri Hiralal, Sorter, Toonka Mine on the 6th June, 1969 was voluntary and its acceptance by Messrs Duduwala and Company, Mica Mine Owners, Bhilwara, was *bona fide*? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. 24/62/69-LR.IV.]

S.O. 4690.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Duduwala and Company (Private) Limited, Mica Mine Owners, Bhilwara, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Gopal Narain Sharma as Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the resignation tendered by Shri Bhur Singh, Chowkidar, Toonka Mines on the 6th June, 1969 was voluntary and its acceptance by Messrs Duduwala and Company, Mica Mine Owners, Bhilwara was *bona fide*? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. 24/63/69-LR.IV.]

S.O. 4691.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Duduwala and Company (Private) Limited, Mica Mine Owners, Bhilwara, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Gopal Narain Sharma, as Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Duduwala and Company, Mica Mine Owners, Bhilwara in terminating the services of Shri Salagram, Black Smith, from their Tookka Mica Mine with effect from the 16th June, 1969 was legal and justified and if not, to what relief the workman is entitled?"

[No. 24/64/69-LR.IV.]

New Delhi, the 13th November 1969

S.O. 4692.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pure Sitalpur Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Pure Sitalpur Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan was justified in stopping the following workmen from work from the dates shown against each and dismissing them with effect from 3rd September 1968? If not, to what relief are the workmen entitled?"

<i>Name of workmen</i>	<i>Date of stoppage</i>
1. Shri Ram Prem Singh, Shot Firer	16-5-1968.
2. Shri Ram Prasad Yadav, Line Mistry	28-5-1968.
3. Shri Yogindar Singh, Friction Roller Mazdoor	16-5-1968.
4. Shri Mahadev Singh, Underground Trammer	16-5-1968."

[No. 6/30/68-LR.II.]

S.O. 4693.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Selected Samla Colliery, Post Office Pandaveshwar, District Burdwan, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the demand of the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj for reinstatement of the workers as given below with effect from the dates shown against each is justified?"

Sl. No.	Name of the worker	Designation	Date
1	Shri Ramatur Yadav	Chaprasai	20-5-69
2	" Sudhiram Yadav	Do.	20-5-69
3	" Amar Singh	Do.	20-5-69
4	" Bahadur Yadav	Do.	20-5-69
5	" Ramahari Singh	Do.	20-5-69
6	" Pahari Singh	Do.	20-5-69
7	" Ramgan Singh	Do.	20-5-69
8	" Barai Pandey	Do.	20-5-69
9	" Rajkishori Singh	Do.	20-5-69
10	" Sitaram Dubey	Do.	20-5-69
11	" Mahesh Gore	Do.	20-5-69
12	" Raghabendra Singh	Do.	20-5-69
13	" Babulal Singh	Do.	20-5-69
14	" Durga Prasad Tewari	Do.	20-5-69
15	" Kashi Narh Singh	A/Sird	15-5-69
16	" Dinanath Chard	Do.	15-5-69
17	" Saram Gope	L/Supr.	21-5-69
18	" Sitala Ahir	Do.	21-5-69
19	" Satdeo Singh	Do.	21-5-69
20	" Ahamed Mia	Trammer	21-5-69
21	" Shyam Behari Kohar	Do.	21-5-69
22	" Dinanath Kohar	Do.	21-5-69
23	" Sadannand Dhar	Do.	21-5-69
24	" Mahendra Yadav	Do.	21-5-69
25	" Ramaga Yadav	Do.	21-5-69
26	" Ram Chhabila Choubey	Do.	21-5-69
27	" Durbijoy Yadav	L/Mazdoor	21-5-69
28	" Kedar Pandey	H/Khal	21-5-69
29	" Algo Mian	Loader	15-5-69
30	" Bhatan Tanti	Do.	15-5-69
31	" Tejendra Singh	Do.	15-5-69
32	" Ramchandra Yadav	Chaprasai	20-5-69
33	" Madan Singh	L/Mazdoor	18-5-69
34	" Sachin Singh	Trammer	18-5-69
35	" Bans Bahadur Singh	Clerk	2-6-69
36	" Ramnath Nunia	Trammer	21-5-69

Is so, to what relief are the workmen entitled ?

[No 6/74/69-LRII.]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 4694.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3562 dated the 27th August, 1969, published on page 3767 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th September, 1969,—

(i) in line 3, for "Messrs Bengal Coal Company Limited" read "Messrs New Beerbhoom Coal Company Limited";

(ii) in lines 14 and 15, for the words "Messrs Bengal Coal Company Limited" read "~~Messrs~~ New Beerbhoom Coal Company Limited".

[No. 6/39/68-LRII.]

P. C. MISRA, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 4695.—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of regulation 11 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961, the Central Government hereby appoints Shri P. N. Vijaya Raghavan, Superintendent, Mysore/Champion Reef Amalgamated Mine, Kolar Gold Field, Ooragaum as member of the Board of Mining Examinations vice Shri N. S. Claire resigned and make the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment S.O. No. 2631 dated the 26th July, 1967 namely:—

In the said notification, for item 3 the following item shall be substituted, namely:—

“Shri P. N. Vijaya Raghavan, Superintendent, Mysore/Champion Reef Amalgamated Mine, Kolar Gold Field, Ooragaum”.

[No. 3/12/69-MI.]

J. D. TEWARI, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 4696.—Whereas the Central Government was satisfied that—

(1) Messrs. Dina Nagar Adarsh Conduit Pipe Manufacturers.

(2) Messrs. Dina Nagar Rubber Production Cooperative Society,

were situated in Dina Nagar area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the District of Gurdaspur in the State of Punjab;

And, whereas by virtue of their location in a sparse area, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 798, dated the 8th March, 1968;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Dina Nagar area in the District of Gurdaspur in the State of Punjab has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification, against serial No. 3, the entry “Dina Nagar” in column 3 and the corresponding entries in column 4 shall be omitted

[No. F. 6/68/69-HI.]

S.O. 4697.—Whereas the Central Government was satisfied that—

(1) Messrs. Gupta Brothers Registered.

(2) Messrs. Northern India Rubber Mills.

(3) Messrs. Universal Indus.

(4) Messrs. Bharat Indus.

were situated in Dina Nagar area which was a sparse area, (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the District of Gurdaspur in the State of Punjab;

And, whereas by virtue of their location in a sparse area, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 135, dated the 5th January, 1962;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Dina Nagar area in the district of Gurdaspur in the State of Punjab has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification, against serial No. 5, the entry "Dina Nagar" in column 3 and the corresponding entries in column 4 shall be omitted.

[No. F. 6/68/69-HI].

S.O. 4698.—Whereas the Central Government was satisfied that Messrs Gupta Rubber Mills was situated in Dina Nagar area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Gurdaspur in the State of Punjab;

And, whereas by virtue of its location in a sparse area, the aforesaid factory was granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Department of Social Security No. S.O. 3230 dated the 25th September, 1965;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Dina Nagar area in the district of Gurdaspur in the State of Punjab has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification, against serial No. 5, the entry "Dina Nagar" in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be omitted.

[No. F. 6/68/69-HI.]

S.O. 4699.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government having regard to the location of the factories specified in the Schedule hereto annexed in sparse areas in the State of Orissa, hereby exempts the said factories from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcement of the provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of Area	Name of the Factory
1	2	3	4
1	Balasore	Kantapal	Shree Ram Chuda and Rice Mills.
2	Cuttack	Jagatpur	1. M/s. Tripty Drinks (P) Ltd. 2. Shree Lakshmi Narain & Sons
		Kendrapara	Shri Baldev Jew Power Loom Weaver's Co.-op. Society.
3	Koraput	Nowrangpur	The Nowrangpur Saw Mill.
		Malkangiri	M/s. Zonal Workshop (Dandakaranya Project).

1	2	3	4
4	Phulbani	Phulbani	The Orissa Road Transport Co.
5	Sundergarh	Santoshpur	M/s. Re-Rolling Mills.
		Biramitrapur	M/s. Mittal Biscuit & Company.
		Sundergarh	The State Transport Workshop.

[No. F. 6/12/68-HI.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)*New Delhi, the 7th November 1969*

S.O. 4700.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the Industrial dispute between the employers in relation to Cantonment Board, Dinapore and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1969.

**THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 3)
AT DHANBAD**

REFERENCE NO. 37 OF 1969

PRESENTS:

Sri Sachidanand Sinha, M.A.M.L., Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the Cantonment Board, Dinapore.

Vs.

Their workman.

APPEARANCES:

For employers.—Sri A. Bhattacharjee, Executive Officer

For workmen.—Shri B. Sarkar, General Secretary.

INDUSTRY: Cantonment Board.

STATE: Bihar.

Dhanbad, dated the 13th of October, 1969.

AWARD

1. The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Cantonment Board, Dinapore and their workman, by its order No. 9/10/68-LRIII, dated the 24th of May, 1969 referred to this Tribunal under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the schedule annexed thereto. The Schedule is extracted below:—

SCHEDULE

“Whether the action of the Cantonment Board Dinapore in terminating the services of Sri Chandrika Singh, Electrician, with effect from the 20th April, 1968 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. The employers as well as the workman filed their respective written statement. It is unnecessary to state the respective cases of the parties because the dispute has been settled. On the date fixed for hearing the parties turned up with a joint petition of settlement. According to the terms of compromise Sri Chandrika Singh, Electrician will be reinstated within one month from the date

of publication of the award but he will not be entitled to get his pay and allowances from the date of dismissal to the date of his reinstatement. He will be entitled to get the benefit of leave increment and other benefit of his service which will be restored to him.

3. The terms are satisfactory and reasonable and are accepted. Accordingly an award is made in terms of the joint petition of settlement, a copy of which is annexed with the award. It may be submitted to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) SACHIDANAND SINHA, Presiding Officer.

'ANNEXURE A'

BEFORE HON'BLE SACHIDANAND SINHA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
NO. 3

REFERENCE NO. 37 OF 1969

In the matter of Industrial Dispute between the Dinapore Cantonment Board (in relation to employer).

Versus

Their workmen,

The management and the workmen represented by Shri Barun Sarkar, General Secretary, Dinapore Cantt. Board Workers' Union has come to an amicable settlement on the above noted Industrial Dispute to maintain healthy relation between the employer and employee.

Both parties most respectfully sheweth:

1. That Sri Chandrika Singh, Electrician will be reinstated within one month from the date of the publication of award.

2. He, Sri Chandrika Singh agrees to forgo his pay and allowances from the date of dismissal to the date of joining duty and for which he will not claim on any future date.

3. He, Sri Chandrika Singh will get the benefit of leave increment and other benefit of his service which will be restored to him.

4. He, Sri Chandrika Singh undertakes to work faithfully and sincerely in the best interest of the Board.

(Sd.) Illegible

Executive Officer,
Cantonment Board,
Dinapore Cantt.

(Sd.) Illegible,

Signature of workman.

(Sd.) Illegible

Signature of General Secretary,
Dinapore Cantt. Board Workers'
Union.

[No. 9/10/69-LRIII (LRI).]

ORDERS

New Delhi, the 7th November 1969

S.O. 4701.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Marine and General Insurance Company Limited, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Marine and General Insurance Company Limited, Calcutta, in terminating the services of its employee Sk. Sahabbudin, Driver, with effect from the 26th April, 1969, is justified? If not, to what relief Sk. Sahabbudin is entitled?"

[No. 40/15/69-L.R.-I.]

New Delhi, the 12th November 1969

S.O. 4702.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the Chartered Bank, Kanpur and their workmen represented by the U.P. Bank Employees Union, Kanpur;

And, whereas the said employers and workmen have, under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the dispute to arbitration by arbitration agreement and have forwarded to the Central Government under sub-section (3) of section 10A of the said Act a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 6th November, 1969.

Agreement

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of Parties:

Representing employers: Shri A. K. Kacker, Accountant, The Chartered Bank, Kanpur.

Representing workmen:

Shri Harmangal Prasad, Secretary, U.P. Bank Employees Union, Kanpur Unit.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri V. P. Gupta, Regional Labour Commissioner (Central), 7/201, Swaroop Nagar, Kanpur.

(i) Specific matters in dispute:—

"Whether the management of the Chartered Bank, Kanpur is justified in non-payment of Special Assistant allowance of Rs. 75/- per month to Shri Mahendra Nath Nigam of the Chartered Bank, Kanpur from 22nd December 1968 and not to change his designation from Clerk to Special Assistant? If not, to what relief the workman is entitled?"

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

(a) The Manager, The Chartered Bank, The Mall, Kanpur.

(iii) The name of the Union, if any, representing the workmen in question.

(a) The Secretary, U.P. Bank Employees Union, 36/8, Hata Ram Mohan, Kanpur.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected—One.

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute—One.

The decision of the arbitrator shall be binding on us.

We further agree that ————— in the case the arbitrators are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of 31st March, 1970 or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to

arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Representing employers.

(Sd.) A. K. KACKER, 27th October, 1969.
Accountant, The Chartered Bank,
The Mall, Kanpur.

Representing workmen.

(Sd.) HAR MANGAL PRASAD,
27th October, 1969.
Secretary, U.P. Bank
Employees Union, Kanpur
Unit.

Witnesses.

1. (Sd.) Illegible
27th October, 1969.

2. (Sd.) Illegible
27th October, 1969.

[No. 24/26/69/LRIII.]

S.O. 4703.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the National and Grindlays Bank Ltd. Kanpur and their workmen represented by the U.P. Bank Employees Union Kanpur;

And, whereas the said employers and workmen have, under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the dispute to arbitration by arbitration agreement and have forwarded to the Central Government under sub-section (3) of section 10A of the said Act a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby published the said arbitration agreement which was received by it on the 6th November, 1969.

Agreement

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act 1947)

BETWEEN

Names of Parties:

Representing employers:

Mr. A. N. Maclean, Manager, National and Grindlays Bank Limited, Kanpur.

Representing workmen:

Shri Harmangal Prasad, Secretary

Shri S. N. Chakravarty, Vice-President, U.P. Bank Employees Union, Kanpur.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri V. P. Gupta Regional Labour Commissioner (Central), 7/201 Swaroopnagar, Kanpur-2.

(i) Specific matters in dispute.

"Whether the management of the National and Grindlays Bank Limited, Kanpur is justified in withdrawing *vide* their letter dated 20th August 1969 the present practice of night refreshment allowance paid in cash on each half-yearly closing to its workmen at Kanpur: If not, to what relief the workmen are entitled?"

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

1. The Manager, National and Grindlays Bank Limited, The Mall, Kanpur.

(iii) The Name of the Union, if any, representing the workmen in question.

The Secretary, U.P. Bank Employees Union, 36/8 Hata Ram Mohan, Kanpur.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected. 99.

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute. 99.

The decision of the arbitrator shall be binding on us.

We further agree that.....in the case the arbitrators are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of 31st March 1970 or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

(Sd.) A. N. MACLEAN,
representing employer.

(Sd.) HARMANGAL PRASAD,
23rd October, 1969.
(Sd.) S. N. CHAKRAVARTY,
representing the workmen.

Witnesses:

1. (Sd.) Illigible
2. (Sd.) Illigible.

[No. 24/27/69/LRIL.]

New Delhi, the 13th November 1969

S.O. 4704.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Beas Dam Project and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri P. P. R. Sawhney shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the management of the Beas Dam Project, Talwara was justified in dismissing Shri Gopi Chand Rana from service with effect from the 23rd June, 1966? If not, to what relief is the workman entitled?”

[No. 4/22/69/LR.III.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 12th November 1969

S.O. 4705.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961) read with clause (iii) of rule 3 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963, the Central Government, in consultation with the Government of the State of Andhra Pradesh, hereby appoints Shri G. Bhupathy, Member of the Legislative Assembly, Andhra Pradesh, Nerella, Karimnagar District, to be a Member of the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the State of Andhra Pradesh, constituted by the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. S.O. 4260 dated the 18th November, 1968, and makes the following amendment in the said notification, namely:—

In the said notification, against serial number 3, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Shri G. Bhupathy, M.L.A., Nerella, Karimnagar District, Andhra Pradesh”.
—Member of the Legislative Assembly.

[No. F. 10/26/68-M.III.]

C. R. NAIR, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 4th November 1969

S.O. 4706.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Lima Leitao & Company Limited, Vasco-da-Gama and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, (No. II), Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

THE SCHEDULE

"(1) Whether the action of the management of Messrs Lima Leitao and Company Limited, Vasco-da-Gama in retrenching the following workmen with effect from 31st December, 1968 and 1st January, 1969 is justified;

(2) If not, to what relief they are entitled to

Name	Designation
1. R. J. Fernandes	General Clerk.
2. S. Mergulhao	Account's Clerk.
3. Yes Want Parackar	Driver.
4. R. N. Kalangutker	Supervisor.
5. J. A. Rodrigues	Tally Clerk.
6. John Fernandes	Tally Clerk.
7. Marlanio Nunes	Tally Clerk.
8. M. L. Adarker	M/L Incharge.
9. Anthony Carvalho	N/L Assistant.
10. Soma Palkar	Foremen
11. Domingos Souza	"
12. Menino A-phonso	"

Lauch Crew

1. Laxman Chodnaker	Tindal
2. Gurudas Custa Naik	Driver.
3. Surya Vithal Poito	Sailor.
4. Ramachandra S. Naik	"
5. Vasudeo Parob	Tindal.
6. Tulsidas M. Corjuenker	Driver.
7. Janarathan C. Naik	Sailor.
8. Kasinath L. Seth	"
9. Sabs Jambo Mojo	"

[No. 29/39/69-LWI-III.]

C. RAMDAS, Dy. Secy.

(Department of Rehabilitation)

(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 11th November 1969

S.O. 4707.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section 1 of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under

Sub-Section 4 of Sections 24, 28 and 33 of the said Act, shall be exercisable also by the Secretary to the Government of Haryana, Rehabilitation Department, in respect of proceedings pertaining to (i) agricultural lands and shops in any rural area including houses, cattle sheds and vacant sites forming part of the Compensation Pool, and (ii) the properties referred to in the Notification of the Government of India in the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) No. 3(37)/L & R-63A dated 5th March, 1964, situate within the State of Haryana, subject to the condition that he shall not exercise any of such powers in relation to any matter in which an order has been made him in any other capacity.

This supersedes this office Notification dated 25th August/2nd September, 1969.

[No. F. 3(2)/L & R/69.]

S. K. GANGOPADHYAY, Jt. Secy.